twitter.com/divyadelhi | facebook.com/divyadelhi | infodivyadelhi@gmail.com | Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

DD

# दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | सोमवार, 14 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 238, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

## बिहार वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोगों की भी बड़ी संख्या

### अवैध प्रवासियों के नाम अंतिम निर्वाचन सूची में नहीं शामिल किए जाएंगे

एजेंसी

**पटना** : बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य जारी है। पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि बिहार में अवैध अप्रवासी भी यहां के मतदाता बन गए हैं। अब इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की गहन समीक्षा के दौरान पाया कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों बड़ी संख्या में शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर इसकी जांच की तो पता चला। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि अवैध प्रवासियों के नाम अंतिम निर्वाचन सूची में नहीं शामिल किए जाएंगे। यह 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, इसके लिए ऐसे लोगों की उचित जांच एक अगस्त के बाद की जाएगी। चुनाव आयोग अंततः भारत भर में विदेशी अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा करेगा, जिसमें उनके जन्म स्थान की जांच की जाएगी। बिहार इस वर्ष चुनावों में जाएगा, जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे पांच अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 में निर्धारित हैं।

**243 विधानसभा क्षेत्रों में बारीकी से निगरानी की जा रही है**

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और 963 सहायक ईआरओ (एईआरओ) सहित क्षेत्र स्तरीय टीमों की निर्वाचन अधिकारी की ओर से बारीकी से निगरानी की जा रही है। चुनाव आयोग के इन प्रयासों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 1.5 लाख बीएलए भी घर-घर जाकर हर मौजूदा मतदाता को शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं,

अब तक 80.11% मतदाता जमा कर चुके हैं गणना प्रपत्र पाया गया है।

**मतदाता सूची वितरण का काम पूरा**

100 फीसदी मुद्रण पूरा होने और अपने पते पर पाए गए सभी मतदाताओं को मतदाता सूची वितरण का काम लगभग पूरा होने के बाद, आज शाम 6 बजे तक संग्रह 6,32,59,497 या 80.11 फीसदी पार कर गया। इसका मतलब है कि बिहार में हर 5 में से 4 मतदाताओं ने मतदाता सूची जमा कर दी है।

## 10 दिनों में 1.82 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की अमरनाथ यात्रा

एजेंसी

**श्रीनगर।** पिछले 10 दिनों में 1.82 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं और रविवार को 7,049 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.82 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमें उम्मीद है कि आज यह संख्या दो लाख को पार कर जाएगी क्योंकि यात्रा सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। गुरुवार को पहलगाम में छड़ी मुबारक (भगवान शिव की पवित्र गदा) का भूमि पूजन किया गया। छड़ी मुबारक के एकमात्र संरक्षक महंत स्वामी दीपेंद्र गिरि के नेतृत्व में साधुओं के एक समूह द्वारा श्रीनगर स्थित दशनामी अखाड़ा भवन से पहलगाम तक छड़ी मुबारक को ले जाया गया। पहलगाम में छड़ी मुबारक को गौरी शंकर मंदिर ले जाया गया जहाँ भूमि पूजन किया गया। छड़ी मुबारक 9 अगस्त को पवित्र गुफा मंदिर पहुँचेगी जब यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न होगी।

अधिकारियों ने इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है क्योंकि यह यात्रा 22 अप्रैल के कायराना हमले के बाद हो रही है जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन मैदान में आस्था के आधार पर 26 नागरिकों को अलग-थलग कर उनकी हत्या कर दी थी।

## मध्य प्रदेश में चल रहा है निवेशकों का यज्ञ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

एजेंसी

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेशकों का यज्ञ चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेशकों से समर्थन मिल रहा है। प्रदेश सरकार आकर्षक औद्योगिक और निवेश नीतियों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। विगत एक वर्ष में प्रदेश के संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कोनक्लेव और देश के प्रमुख औद्योगिक नगरों में रोड शो आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को दुबई और स्पेन की 7 दिवसीय यात्रा पर जाने से पहले अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ था। निवेश आकर्षित करने का यह सिलसिला लगातार जारी है और हाल ही में सूरत, लुधियाना और जोधपुर में भी सफल रोड शो का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 13 से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन की यात्रा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा के माध्यम से विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश संभावनाओं और आकर्षक निवेश नीतियों से अवगत कराया जाएगा। इस यात्रा के दौरान दुबई और स्पेन के निवेशकों के बीच राज्य की औद्योगिक निवेश के संबंध में ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे मध्यप्रदेश विदेशी निवेश में शीर्ष राज्य बने। प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योग- भारी उद्योग, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम, आइ टी, इत्यादि तथा पर्यटन, वन, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही प्रदेश के विभिन्न अंचलों जैसे चंबल, महाकौशल, विंध्य, मालवा, बुंदेलखंड की विशेषताओं के आधार पर अनुकूल प्लानिंग के साथ विदेशी सरकारों के सौजन्य से विदेशी निवेशकों से चर्चा की जाएगी।

## सरकार आतंकवाद प्रभावित परिवारों को उनकी जब्त संपत्तियां जल्द लौटाएगी: एलजी

एजेंसी

**बारामूला।** जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि आतंकवाद प्रभावित परिवारों से जुड़े सभी अपंजीकृत मामलों की जांच करके जब्त की गई संपत्तियों को उनके असली मालिकों को वापस की जाएगी। आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद उपराज्यपाल सिन्हा ने बारामूला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद इन परिवारों के पात्र सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों को वित्तीय सहायता नहीं मिली है, उन्हें अब सहायता प्रदान की जाएगी। हम स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। उन्होंने अनंतनाग में कई आतंकवाद प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद अपने भावनात्मक अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि परिवार बहुत भावुक थे।

उनमें से कई को पात्रता होने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं दी गई, जबकि यह उनका अधिकार था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ने उन मामलों की समीक्षा करने का भी फैसला किया है, जहां एफआईआर दर्ज नहीं की गई या संपत्ति जब्त की गई। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और जब्त की गई संपत्तियां वापस कर दी जायेंगी।

## पाप करने वाले लोग अब साधु बन रहे : शेखावत

**जोधपुर।** केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर कांग्रेस पर पलवार किया। शेखावत ने पूछा कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तय हार को टालने के लिए, कहीं गलत नैरेटिव न बन जाए, छात्रसंघ चुनाव को रोकने का पाप किसने किया था? वह पाप करने वाले लोग अब यहां पर साधु बन रहे हैं। शेखावत ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं उछलना चाहिए। छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस की मांग से जुड़े प्रश्न पर शेखावत ने कहा कि मैंने फलोदी में एक दिन पहले भी यह बात कही थी कि कुछ लोगों को कानून, संविधान...सब, जब वो सत्ता से बाहर होते, तब याद आते हैं।

## स्वच्छ भारत का सपना बना संकल्प: शिवराज

एजेंसी

**भोपाल।** केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में मध्य प्रदेश ने इस वर्ष भी अपनी विजय पताका फहराई है। प्रदेश के 8 शहरों को इस राष्ट्रीय आयोजन में सम्मानित किया जाएगा। विशेषकर बुधनी और शाहगंज नगर परिषद को पुरस्कारों को लिए नामित किया गया है। इस उपलब्धि पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता ही सेवा है...। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ह्यस्वच्छ भारतह्न का सपना जन-जन का संकल्प बन चुका है। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हाल ही में जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में बुधनी और शाहगंज को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया है। बुधनी नगर परिषद को "सुपर स्वच्छ लीग सिटी" की नई श्रेणी में कन्सीसटेंट परफार्मर के रूप में नामित किया गया है। यह उपलब्धि सतत प्रयास, जनभागीदारी और समर्पित प्रशासन का प्रमाण है। साथ ही, शाहगंज नगर परिषद को प्रेसिडेंशियल अवार्ड की प्रतिष्ठित श्रेणी में चयनित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल नगर निकाय की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रमाण है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग का भी उत्सव है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

## हिमाचल में 14 से 17 जुलाई तक कुछ इलाकों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे अवरुद्ध

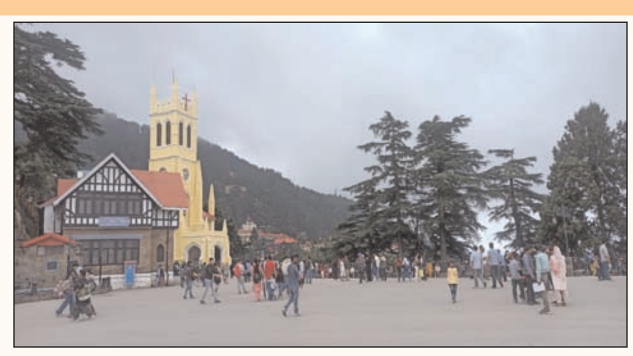

**शिमला**

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में रविवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों में मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने से भारी बारिश में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। जोत में सर्वाधिक 27 मिमी, कुफरी में 24 मिमी, शिमला में 15 मिमी, चौपाल में 13 मिमी और कंडाघाट में 11 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार 14 से 17 जुलाई तक राज्य में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है और इस अवधि में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। सिरमौर जिले के हरिपुरधार क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में दो वाहन आ गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि जल शक्ति विभाग का भवन भी खतरे की जद में आ गया है। भूस्खलन से हरिपुरधार-कुपवी मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। वहीं, मंडी जिले में बीती रात से चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेशभर में भूस्खलन के कारण 200 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हैं। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां सबसे अधिक मार्ग बाधित हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 300 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर और 700 से अधिक पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मंडी जिले में अकेले 102 ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं और 175 पेयजल योजनाओं पर असर पड़ा है, जबकि कांगड़ा जिले में 612 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं और हमीरपुर में 166 ट्रांसफार्मर ठप हैं।

## ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी वोटरों की सूची क्यों नहीं सौंपी: बीजेपी

एजेंसी

**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और फर्जी मतदाताओं को लेकर राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी ने अब तक वह सूची क्यों नहीं सौंपी, जिसके बारे में उन्होंने 20 साल पहले लोकसभा में दावा किया था। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चार अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने संसद में कहा था कि बंगाल में घुसपैठ अब एक आपदा बन चुकी है। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटरों की सूची है। यह बहुत गंभीर मामला है। लेकिन अब 20 साल बीतने के बाद भी उन्होंने वह सूची कभी पेश नहीं की। आखिर ममता बनर्जी क्या छिपा रही हैं? इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्य में फर्जी मतदाताओं की भारी संख्या को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों जैसे कूचबिहार, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में जनसंख्या में अस्वाभाविक बढ़ोतरी घुसपैठ का संकेत देती है।उन्होंने कहा कि बंगाल की मतदाता सूची को बिहार की तरह साफ-सुथरा करने की जरूरत है। जिस तरह बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, वैसा ही अभियान बंगाल में भी शुरू किया जाना चाहिए, तृणमूल सरकार उन्हें शरणार्थी मानती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे घुसपैठिए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था। इस निर्णय का तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकती है। भाजपा के इन आरोपों से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर घुसपैठ, पहचान और मतदाता सूची की शुद्धता जैसे संवेदनशील मुद्दे केंद्र में आ गए हैं।

## मुख्यमंत्री का ग्रीन एण्ड क्लीन कांवड़ यात्रा का सपना हो रहा साकार

एजेंसी

**हरिद्वार।** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में कांवड़ यात्रा को स्वच्छ, सुन्दर व पर्यावरणीय अनुकूल बनाने के लिए विशेष पहल की गई है। जिसके अन्तर्गत कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता व पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन एण्ड क्लीन कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए अल्प समय में ही कांवड़ यात्रा मोबाइल एप का निर्माण भी किया गया है। जिस पर कांवड़ियों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया । देश के विभिन्न कोनों से कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग एवं कांवड़ मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं यथा-पेयजल, शौचालय, स्नान, सफाई व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आदि व्यवस्थाओं की कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

**डीएम तथा एसएसपी स्वयं ले रहे पल-पल की खबर**

सफलतापूर्वक आयोजन हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा स्वयं विभिन्न क्षेत्रों का लगातार औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को परख के साथ ही विभिन्न माध्यमों से भी यात्रा मार्ग पर संचालित गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए पल-पल की खबर रखी जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा का धार्मिक, आध्यत्मिक व सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले को रूप से संचालित करने एवं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुखद व सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष इन्तजाम किये गये हैं।

## शिमला : हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध बागीचों पर चला बुलडोजर, 400 से ज्यादा फलदार पेड़ काटे

शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर शिमला जिले के कोटखाई और कुमारसैन में वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने की बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। वन विभाग की टीम ने कोटखाई के चैथला गांव में सेब के करीब 100 पेड़ काटे, जबकि कुमारसैन के सराहन गांव में सेब, नाशपाती और चेरी के करीब 320 पेड़ काटे गए। पुलिस की सुरक्षा के बीच वन विभाग ने ये कार्रवाई शनिवार देर रात तक अमल में लाई। चैथला गांव में लोगों ने लगभग 275 बीघा वन भूमि पर कब्जा कर सेब के करीब 3800 पेड़ लगा रखे हैं। इस कार्रवाई में वन विभाग की 15 सदस्यीय टीम, 5 कटिंग मशीनें और 6 रिजर्व फोर्स के जवान तैनात रहे। बारिश के चलते कुछ रुकावटें जरूर आईं, लेकिन देर शाम तक तीन खसरा नंबर की जमीन कब्जा मुक्त करवा ली गई। एसडीएम कोटखाई मोहन शर्मा ने रविवार को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वन भूमि पर सेब के अवैध बगीचों को हटाया जा रहा है। यह कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ की जा रही है। वहीं डीएफओ ठियोग मुनीश रामपाल ने कहा कि चैथला गांव में कुल 3800 पेड़ हटाए जाएंगे, ताकि वन भूमि को उसके मूल स्वरूप में लौटाया जा सके। उधर कुमारसैन तहसील के सराहन गांव में भी हाईकोर्ट के आदेश पर सेब, नाशपाती और चेरी के करीब 320 पेड़ काटे गए। आरओ कुमारसैन अरुण कुमार ने बताया कि ह्लचार लोगों के बगीचों में कार्रवाई की गई है, शेष पर 14 जुलाई को कार्रवाई होगी। एक अवैध मकान को भी कब्जे में लेकर तालाबंदी की गई है। प्रशासन ने किसी भी विरोध की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने चैथला गांव की सीमाओं में 11 से 18 जुलाई तक हर तरह के लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी हथियार रखने और ले जाने पर रोक लगा दी है। जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं, उन्हें 12 जुलाई तक कोटखाई पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। यह आदेश पुलिस और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अतीत में भी अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

# एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान हादसे पर 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, जेट ईंधन स्विच हवा में 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हो गए और एक पायलट को यह कहते हुए सुना गया कि मैंने ईंधन बंद नहीं किया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 अहमदाबाद में 12 जून को भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही सकेंड में लोगों की जान चली गई। मृतकों में 229 यात्री, 12 क्रू सदस्य और 19 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद एयरलाइन ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में लिखा है, एयर इंडिया एआई-171 हादसे से प्रभावित परिवारों और अन्य लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं, इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें एएआईबी द्वारा आज, 12 जुलाई, 2025 को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सूचना है। एयर इंडिया नियामकों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। हम एएआईबी और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूर्ण सहयोग जारी रखेंगे। इस जांच की सक्रिय प्रकृति को देखते हुए, हम विशिष्ट विवरणों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और ऐसी सभी पूछताछ एएआईबी को भेज रहे हैं।

एयर इंडिया की एआई-171 विमान हादसे के प्रमुख घटनाक्रम

एएआईबी ने इस हादसे पर 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई सारे चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐसे में शुरुआत से लेकर अबतक इस विमान हादसे में क्या-क्या हुआ एक नजर डालते हैं।

-12 जून को टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया का करीब 12 साल पुराना बोइंग 787-8 विमान वीटी-एएनबी, उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद गुजरात के अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर पर गिरकर हादसे का शिकार हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था।

-इस विमान में चालक दल के 12 सदस्यों समेत कुल 242 लोग सवार थे। हादसे में केवल एक यात्री बच पाया। विमान दुर्घटना में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के अलावा भी कई लोगों की जानें गई। विमान हादसे में कुल 260 लोग मारे गए।

-इस हादसे में जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश (45) '11ए' सीट पर बैठे थे। यह सीट आपातकालीन निकास द्वार के पास की खिड़की वाली सीट थी। वह ब्रिटेन के नागरिक हैं।

-अहमदाबाद की यह विमान दुर्घटना बोइंग के सबसे ज्यादा बिकने वाले 787 विमान की पहली ऐसी घातक दुर्घटना है जिसमें विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया।

- विमान हादसों की जांच करने वाली एजेंसी एएआईबी ने 13 जून को इस विमान हादसे की जांच शुरू की और एक बहु-विभागीय टीम गठित की।

-केंद्रीय गृह सचिव की अयक्षता में एक उच्च स्तरीय बहु-विभागीय समिति 13 जून को गठित की गई जिसका उद्देश्य विमान दुर्घटना के पीछे के कारणों की जांच करना और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यापक सुझाव देना था।

-इस विमान के 'कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर' (सीवीआर) और 'फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर' (एफडीआर) बरामद किए गए।

## माकपा छद्म युद्ध के लिए राज्य चुनाव आयोग का कर रही है इस्तेमालः भाजपा

**एजेंसी**

**तिरुवनंतपुरम।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई ने शनिवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित कर रही है ताकि मतदाताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने से रोका जा सके। भाजपा के प्रदेश महासचिव एमटी रमेश ने आज यहां एक बयान जारी करके यह आरोप लगाया। उन्होंने माकपा पर राज्य चुनाव आयोग का उपयोग छाया युद्ध के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया के कार्य में राजनीतिक कारणों से विलंब किया जा रहा है।श्री रमेश ने कहा, जानबूझकर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। माकपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं को भाग लेने से रोकने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल प्रदेश इकाई ने कर रही है। भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को दूर करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि इन मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने से कई पात्र लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।जवाब में, राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां ने भाजपा नेताओं को सूचित किया कि इस मामले पर चर्चा के लिए 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। श्री रमेश ने सरकार द्वारा मतदाता सूची प्रक्रिया में कथित हेराफेरी को रोकने का आह्वान किया और संभावित गंभीर अनियमितताओं की चेतावनी दी है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता-अनुकूल उपाय लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ऐसा करने में असमर्थ होता है तो भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। उनका बयान चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी एवं पारदर्शिता को लेकर चिंताओं को उजागर करता है। अदालत जाने की उनकी धमकी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है। भाजपा ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान मतदाता पंजीकरण प्रणाली जटिल और उपयोगकर्ता-अनुकूल नहीं है। पार्टी ने जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक सरल और ज्यादा सुलभ प्रणाली लागू करने की मांग की।

## रेखा गुप्ता ने जिलाधिकारी से इमारत ढहने की रिपोर्ट तलब की

**नई दिल्ली।** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में इमारत गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स कहा, सीलमपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण इमारत ढहने की खबर मिली है। जैसा कि जानकारी मिली है, चार लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया है। यह अत्यंत दुखद है कि इस घटना में दो अनमोल जानें चली गईं। कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जिलाधिकारी को घटना पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मृतकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम इलाके में आज एक इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि आठ लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

## पद्मश्री सानु लामा का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया

**गंगटोक।** सिक्किम के एक वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सानु लामा का शनिवार सुबह सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और वरिष्ठ साहित्यकारों लामा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज जारी अपने शोक संदेश में कहा कि वरिष्ठ साहित्यकार सानु लामा के निधन का समाचार सुनकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने सानु लामा के निधन को साहित्य जगत और सिक्किम के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने वरिष्ठ साहित्यकार सानु लामा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि नेपाली भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित सानु लामा के जीवन ने हम सभी पर गहरी छाप छोड़ी है। उनकी रचनात्मक प्रतिभा, काव्यात्मक सौंदर्य और नेपाली साहित्य के प्रति समर्पण ने सिक्किम की साहित्यिक परंपरा को समृद्ध किया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका गौरव बढ़ाया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सानु लामा के निधन पर गहरा दुख और हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई है। भाजपा सिक्किम ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लामा ने नेपाली साहित्य में अनगिनत मोती बिखेरे हैं और उनकी रचनाओं का अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, असमिया और ओड़िया में अनुवाद हुआ है। सानु लामा के निधन से नेपाली साहित्य और संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है।

# पीएम मोदी ने 16वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

## बोले- युवा राष्ट्र निर्माण के सिपाही

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 16वें रोजगार मेले के तहत देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सिपाही बताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति ÷बिना पर्ची, बिना खर्चे÷ की पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने जोर दिया कि ये युवा %विकसित भारत% के संकल्प को साकार करेंगे। रोजगार मेला केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने पर केंद्रित है। इस पहल की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 से

हुई थी, और अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये नव-नियुक्त युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय समावेशन और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। पीएम मोदी ने कहा, ÷विभाग भले ही अलग हों, लेकिन आपका ध्येय एक है - राष्ट्र सेवा। आप रेलवे में दायित्व निभाएं, देश की सुरक्षा करें, डाक सेवाओं को गांव-गांव पहुंचाएं या स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनें, आपका लक्ष्य विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है।÷

पीएम ने कहा कि अगले 20-25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और युवाओं को अपने करियर को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ना होगा। उन्होंने हाल की अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले दशक में 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया, जिससे न केवल सामाजिक सुरक्षा बढ़ी, बल्कि लाखों नए रोजगार भी सृजित हुए।

## बेंगलुरु भगदड़ मामले में जांच आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, आरसीबी, केएससीए और पुलिस को ठहराया जिम्मेदार

**एजेंसी**

**बेंगलुरु।** बेंगलुरू में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ की घटना पर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दी गयी है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) माइकल डी. कुन्हा की एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) और बेंगलुरु पुलिस के अधिकारियों को घटना के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई सिफारिशें भी की गई हैं। न्यायमूर्ति माइकल कुन्हा की जांच रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और शहर के कई पुलिस अधिकारियों को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कार्यक्रम को इतने कम समय में आयोजित करना असंभव

होने की जानकारी होने के बावजूद इसे आयोजित किया गया। सभी के कर्तव्यों में लापरवाही और निष्क्रियता के कारण यह त्रासदी घटी। विजय उत्सव के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी। पुलिस की व्यापक तैनाती नहीं थी। लाखों की संख्या में प्रशंसकों के आने का अनुमान लगाने में पुलिस, आरसीबी और केएससीए के अधिकारी विफल रहे।

## दिल्ली इमारत हादसाः दो लोगों की मौत, कपिल मिश्रा ने पिछली सरकार पर साधा निशाना

**एजेंसी**

**नई दिल्ली ।** दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में इमारत ढहने से अब तक दो लोगों की मौत हो गई है। आठ लोगों को बचाया गया है। हालांकि, मलबे में दबने से वे चोटिल हुए हैं, जिस कारण इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अभी भी एक से दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वेलकम थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता मजदूर कॉलोनी की ईदगाह रोड पर शनिवार सुबह करीब पौने 7 बजे चार मंजिला इमारत भरभराकर गिरी। जानकारी के अनुसार, मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। इधर, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने स्थिति का आकलन करने के लिए इमारत ढहने वाली जगह का दौरा किया है। कपिल मिश्रा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, यह बहुत दुखद घटना है। दो लोगों को बचाया नहीं जा सका। आशंका है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। गली बहुत संकरी है, सिर्फ डेढ़ फुट चौड़ी, जिससे मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो

पा रहा है। मशीन नहीं पहुंचने के कारण हाथों से मलबा हटाना पड़ रहा है। कपिल मिश्रा ने आईएएनएस को बताया कि आसपास की दो-तीन इमारतों को भी खाली कराया गया है। खतरा है कि मलबा हटाने के बाद ये घर गिर सकते हैं, क्योंकि ये घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं। इस बीच कपिल मिश्रा ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ÷पहले मुस्तफाबाद में गिरी, अब सीलमपुर में गिरी। एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है। पिछले 10 साल में वोटबैंक के कारण भयानक करप्शन का खेल खेला गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बातचीत में कहा, गोपाल राय कहां हैं? क्या गोपाल राय इस हत्या की जिम्मेदारी लेंगे? उनकी देखरेख में ऐसे अवैध निर्माण होते रहे हैं। गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल कहां छिपे हैं? पंद्रह-दस साल तक आप कुर्सी पर बैठे रहे और ऐसे घर बनते रहे।

## द्रौपदी मुर्मू ने देखी फिल्म तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर ने कहा हमारे लिये गर्व का पल

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** बॉलीवुड के जानेमाने चरित्र अभिनेता और फिल्मकार अनुपम खेर का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिल्म तन्वी द ग्रेट देखना उनके लिये गर्व का पल है। फिल्म तन्वी द ग्रेट की खास स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही फिल्म की स्टारकास्ट भी शामिल हुई, जिनमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी, करण टेकर और शुभांगी शामिल थे। अनुपम खेर ने फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशन करने के अलावा इसमें अभिनय भी किया है। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर स्पेशल स्क्रीनिंग की फोटोज शेयर कीं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, यह हमारे लिए गर्व का सबसे बड़ा पल था कि देश की राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर ने हमारी फिल्म देखी और अंत में उसकी सराहना की। यह एक सपना सच होने जैसा था। एक निर्देशक के तौर पर देश के सबसे बड़े पद से ऐसा समर्थन मिलना मेरे लिए सच में कुछ भी हो सकता है वाला पल है। बोमन ईरानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तन्वी द ग्रेट' की टीम के लिए एक गर्वभरा और विनम्र

करने वाला लम्हाज जब देश की राष्ट्रपति ने हमारी फिल्म देखी और तारीफ़ की। ये बहुत ही खास और दुर्लभ मौका था ,ऐसा मौका जो याद दिलाता है कि हम ये सब क्यों करते हैं। ञअनुपमखेरसर, हमें इस अनमोल सफर का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद।÷ फिल्म तन्वी द ग्रेट में शुभांगी दत्त मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अनुपम खेर,जैकी श्रॉफ, बोमन ईरानी, पल्लवी जोशी, करण टैकर और इयान ग्लेन जैसे कलाकार अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्देशन और कहानी अनुपम खेर की है। इस फिल्म का निर्माण अनुपम खेर स्टूडियोज ने एनएफडीसी (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम) के साथ मिलकर किया है। यह फिल्म 18 जुलाई को रिलीज होगी।

## प्रधानमंत्री ने 'मराठा सैन्य परिदृश्यों' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर जताई खुशी

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने पर अत्यधिक गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से 12 ऐतिहासिक किलों की धरोहर देखने का आग्रह करते हुए बताया कि इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है। गमराठा साम्राज्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर से जोड़ते हैं। महान शासक किसी भी अन्याय के आगे न झुकने के अपने साहस से

हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने नागरिकों से मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए इन किलों का दौरा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 2014 में रायगढ़ किले की अपनी यात्रा की यादें भी साझा कीं, जिसमें एक तस्वीर भी शामिल थी जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस संबंध में यूनेस्को की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय इस सम्मान से अभिभूत हैं। इन मराठा सैन्य परिदृश्यों में 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर से जोड़ते हैं। महान शासक किसी भी अन्याय के आगे न झुकने के अपने साहस से हमें प्रेरित करते हैं। मैं सभी से इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का आह्वान करता हूं। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, यहां 2014 में रायगढ़ किले की मेरी यात्रा की तस्वीरें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करने का अवसर मिला।

## बिहार में बुलेट ट्रेन के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण

**एजेंसी**

**पटना।** बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। दिल्ली-हावड़ा (कोलकाता) बुलेट ट्रेन केवल 6.5 घंटे में 1,669 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पटना से दिल्ली की 1,000 किलोमीटर की यात्रा में वर्तमान 13-14 घंटों की तुलना में मात्र 4 घंटे ही लगेंगे। पटना से कोलकाता की 578 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे से अधिक समय लगेगा, जिससे वर्तमान 6 घंटे की यात्रा का समय बहुत ही कम हो जाएगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण, दिल्ली से वाराणसी (लखनऊ और अयोध्या के रास्ते) 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरा चरण वाराणसी से हावड़ा (पटना के रास्ते) तक है। बिहार में बुलेट ट्रेन मौजूदा पटरियों के साथ-साथ चलेगी। बुलेट ट्रेन बनारस से मुगलसराय, बक्सर, पटना, किऊल, आसनसोल होते हुए हावड़ा जाएगी। पटना बिहार का एकमात्र स्टॉप होगा। इसके बाद अगला स्टॉप पश्चिम बंगाल का आसनसोल होगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में अलग से कॉरिडोर नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा रेल ट्रैक के समानांतर दो और हाई स्पीड ट्रैक बिछाए जाएंगे।

# केरल में निपाह को रोकने के लिए कई रणनीतियां तैयार : राजन खोबरागड़े

**एजेंसी**

**तिरुवनंतपुरम।** केरल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजन खोबरागड़े ने कहा कि निपाह के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के लिए कई रणनीतियां तैयार की हैं और उन्हें लागू किया है। डॉ. खोबरागड़े ने कल यहां आयोजित निपाह और अन्य जूनोटिक स्पिलओवर - रोकथाम के लिए स्वास्थ्य रणनीतियों का एकीकरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये टिप्पणियां कीं और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। जंगली जानवरों से मनुष्यों में रोगजनकों के संचरण को 'जूनोटिक स्पिलओवर' कहा जाता है। उन्होंने 2019 से राज्य को प्रभावित करने वाली महामारियों का पता लगाने एवं उनकी रोकथाम करने के राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

पर बल देते हुए वर्तमान परिदृश्य में 'वन हेल्थ' अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डाला और राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्नत वायरोलॉजी संस्थान जैसे संस्थानों से सहयोग मांगा। यह सम्मेलन संक्रामक रोग विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम और केरल वन हेल्थ सेंटर फॉर निपाह रिसर्च एंड रेजिलिएंस के सहयोग से आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की संयुक्त निदेशक डॉ. सिम्मी तिवारी ने उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान (आईएवी) की स्थापना के लिए केरल सरकार को बधाई दी और कहा कि संस्थान ने पहले ही विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली है और संस्थान राज्य तथा देश दोनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने राज्य को अक्सर प्रभावित करने वाले जूनोटिक स्पिलओवर संक्रमणों का समय पर पता लगाने के लिए नैदानिक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें विभिन्न विषयों पर सत्र प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए।

## प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर भगवंत मान की टिप्पणी को भाजपा ने शर्मनाक बताया

एजेंसी

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी ने शर्मनाक बताया है। भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेशों में मिलने वाला सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। चाहे वो कोई भी देश हो, जब भारत के नेतृत्व को वैश्विक मंच पर सिर आंखों पर बैठाया जाता है तो वो क्षण संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता है। मुख्यमंत्री भगवत मान का बयान शर्मनाक और हर भारतीय का अपमान है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में तरुण चुघ ने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का ओछी टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश और स्वयं पंजाब जैसे गौरवशाली राज्य के मुख्यमंत्री पद का अपमान है। उन्होंने कहा कि ऐसा घमंड और ऐसी अभद्रता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवंत मान को देश से माफी मांगनी चाहिए और तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।

## तेज रफ्तार टैक्सी ने सब-इंस्पेक्टर को मारी टक्कर, मौत

**नई दिल्ली।** दिल्ली-गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-9 पर एक दर्दनाक हादसे में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर यशपाल की मौत हो गई। वह थाना पांडव नगर में कार्यरत थे और गश्त के दौरान डीसीपी/ईस्ट ऑफिस कट के पास हादसे का शिकार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें तत्काल मैक्स अस्पताल, वैशाली ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। परिजन अस्पताल पहुंचे। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए टैक्सी ड्राइवर विष्णु यादव (37) को गिरफ्तार कर लिया है। वह सरिता विहार का रहने वाला है। उसके कब्जे से हादसे में इस्तेमाल टैक्सी भी जब्त कर ली गई है। आरोपित को कानूनी कार्रवाई के लिए थाना कल्याणपुरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

## दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र का किया निरीक्षण

**नई दिल्ली।** दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह एवं लोकसभा की सांसद बांसुरी स्वराज ने राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त दौरा कर मौजूदा नागरिक सुविधाओं और मानसून के दौरान की गई तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महापौर राजा इकबाल सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि दौरे के दौरान किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति नहीं पाई गई। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे पूरे मानसून सीजन के दौरान सतर्क रहें। जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और दिल्ली की मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगर निगम दिल्लीवासियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज ने सक्रिय प्रशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में सभी गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरवाएं। साथ ही उन्होंने निगम अधिकारियों को क्षेत्र की स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि आमजन को स्वच्छ वातावरण मिल सकें। निरीक्षण के उपरांत बांसुरी स्वराज एवं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने क्षेत्र के एक निगम पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल की।

## दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरिंग कैडर बनाने का लिया निर्णय

**नई दिल्ली।** दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनाने का निर्णय लिया है। यह विभाग के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है, जिससे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) पर दशकों से चली आ रही निर्भरता समाप्त हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जब अभियंता केवल दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, तो उनकी कार्यशैली और प्रतिबद्धता अपने आप बढ़ेगी। हम एक मजबूत, स्वच्छ और तेज दिल्ली बना रहे हैं और इसके लिए हमें अपनी खुद की टीम चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर के गठन का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और आगामी दिनों में इसे दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही विभाग भर्ती प्रक्रिया और संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता तक हर स्तर पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो सिर्फ दिल्ली पीडब्ल्यूडी के अधीन होंगे। पीडब्ल्यूडी में अब तक कार्यरत अधिकांश अभियंता, कार्यपालक अभियंता (ईई), अधीक्षण अभियंता (एसई) और कनिष्ठ अभियंता (जेई) सीपीडब्ल्यूडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति पर आते थे।

# पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति के समक्ष रखा अपना पक्ष

एजेंसी

**नई दिल्ली।** संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आज संसद भवन एनेक्सी में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए बैठक हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इसपर कानूनी और संवैधानिक विषयों पर अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक संसद की संयुक्त समिति की बंद कमरे में हुई अहम बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक में गंभीर संवैधानिक खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन कई धाराएं अस्पष्ट हैं और इन्हें संसद को

स्पष्ट करना होगा। उनके साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने भी ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। दोनों ने बिल की वैधानिकता को सिद्ध किया, लेकिन स्पष्ट भाषा और सुरक्षा उपायों की सिफारिश की। समिति में विभिन्न दलों के 38 सांसद मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का मसौदा तैयार करना है। इसीलिए हमने ऐसे सम्मानित कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है जो निष्पक्ष रहें और केवल कानून के प्रति प्रतिबद्ध हों। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर रही है। चौधरी ने कहा कि जनता की राय, प्रशासनिक प्रतिक्रिया और संवैधानिक सलाह-सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। यह प्रक्रिया राजनीति से ऊपर है और हमारी रिपोर्ट राष्ट्रीय हित में तैयार की जाएगी। समिति अपना परामर्श जारी रखे हुए है और आने वाले महीनों में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

## अलुआबाड़ी-ठाकुरगंज रेलखंड के दोहरीकरण को मिली मंजूरी

एजेंसी

**नई दिल्ली।** उत्तर बंगाल और बिहार को जोड़ने वाले अलुआबाड़ी-ठाकुरगंज रेलखंड के दोहरीकरण परियोजना को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 342.7 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 19.95 किमी लंबे इस मार्ग पर आगामी तीन वर्षों में पूरी की जाएगी।

इसका उद्देश्य रेल यातायात की क्षमता बढ़ाना और सीमावर्ती व रणनीतिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक यह रेलखंड उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) और किशनगंज (बिहार) जिलों से होकर गुजरेगा। दोहरीकरण परियोजना के तहत कुल चार स्टेशन अलुआबाड़ी रोड जंक्शन, पोठिया, तैयबपुर और ठाकुरगंज जंक्शन को शामिल किया गया है। इसमें 9 बड़े और 6 छोटे पुल, 8 अंडरपास, 25 टन लोडिंग मानक, 1×25 केवी विद्युतीकरण तथा 130 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा तय की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक 'कवच' सिग्नलिंग प्रणाली भी लगाई जाएगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में रक्षा बलों और आपूर्ति तंत्र की तेज़ आवाजाही को यह नया रेल मार्ग सुनिश्चित करेगा।

साथ ही, यह मार्ग दार्जिलिंग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक बेहतर और निर्बाध पहुंच भी प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

परियोजना से माल ढुलाई में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुमान है। पहले वर्ष में 0.296 मिलियन टन, छठे वर्ष में 0.348 मिलियन टन और 11वें वर्ष में 0.408 मिलियन टन माल परिवहन की संभावना जताई गई है।

## कॉमन सर्विस सेंटर की 16वीं वर्षगांठ 16 जुलाई को, अमित शाह करेंगे उद्घाटन

एजेंसी

**नई दिल्ली।** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अपनी 16वीं स्थापना दिवस पर 16 जुलाई को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य समारोह का आयोजन करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि पिछले सोलह वर्षों में सीएससी भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा वितरण प्रणाली बनकर उभरी है, जो आज देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्षगांठ के अवसर पर सीएससी अपने भविष्य की रणनीति को प्रस्तुत करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड तकनीक, और ग्रामीण नवाचार जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल इंडिया को और अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।

इस कार्यक्रम के दौरान सीएससी द्वारा देशभर में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उत्सव आयोजित किए जाएंगे। हजारों विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई), नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्री पार्टनर इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। समारोह में उन वीएलई और समुदाय के नेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने सीएससी के माध्यम से समाज को बदलने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सीएससी ने सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर वर्ष 2022 में नाबार्ड और अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और एलएएमपीएस को सीएससी नेटवर्क से जोड़ा था। इसके तहत इन समितियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जिससे ग्रामीण समुदायों में वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आज सीएससी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधार सेवा, पैन कार्ड, पासपोर्ट आवेदन, बैंकिंग, बीमा, टेलीमेडिसिन, टेली-लॉ, बिजली-पानी बिल भुगतान, शिक्षा, कृषि और ई-कॉमर्स जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह मंच जन-सेवा, डिजिटल साक्षरता और समावेशी विकास का एक मजबूत स्तंभ बन गया है।

## मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भाजपा ने इंडी गठबंधन को घेरा

एजेंसी

**नई दिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर राजद समेत इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। गौरव भाटिया ने कहा कि एसआईआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वोटिंग में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए करारा जवाब है। तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि वे

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानेंगे या नहीं? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? इससे स्पष्ट होता है कि इन नेताओं की सर्वोच्च न्यायालय के प्रति कोई आस्था नहीं है।न्यायालय के टिप्पणी आने के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की भीतरी कलह पर गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार से कर्नाटक की जनता त्रस्त है। जनता सुशासन चाहती है लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार केवल सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। एक नेता कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है, तो दूसरा नेता उस कुर्सी को प्राप्त करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जिस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कर्नाटक की जनता का हो रहा है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

## मिशन कॉटन को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जायेंगे: शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी

**नई दिल्ली।** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सभी हितधारक मिलकर एक दिशा में काम करेंगे और जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को हम 2030 से पहले ही प्राप्त करेंगे। मिशन कॉटन को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जायेंगे। शिवराज सिंह कोयम्बटूर के आईसीएआर- गन्ना प्रजनन संस्थान में कपास उत्पादकता बढ़ाने को लेकर अहम बैठक में बोल रहे थे। बैठक में भारत में कपास का इतिहास, परिदृश्य, चुनौतियां, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगामी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के

वाइस चांसलर, आईसीएआर के महानिदेशकएम. एल. जाट, अधिकारीगण, हितधारक, वैज्ञानिक और किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कपास उत्पादन में कुछ समस्याएं आ रही हैं। अन्य राष्ट्रों के मुकाबले देश में उत्पादन कम हो रहा है। कपास उत्पादन के लिए विकसित बीटी कॉटन किस्म में वायरस अटैक के कारण कई तरह की समस्या पैदा हो गई हैं। उत्पादन बढ़ने की बजाय घट रहा है, जिसके लिए हमें काम करना होगा। दुनिया के बाकी देशों के समान भारत में भी कपास उत्पादन बढ़ाने को लेकर सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लक्ष्यबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। वायरस प्रतिरोधी उन्नत बीज बनाने होंगे। निश्चित समय सीमा में किसानों तक इन उन्नत किस्म के बीज की पहुंच सुनिश्चित भी करनी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार उन्नत किस्म के बीज तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन उचित समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पाते। इस काम की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों को पूरी ताकत से काम करना होगा। बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में जाकर कपास उत्पादक किसानों से बातचीत की और हितधारकों से परामर्श करते हुए उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में भी जाना।

## केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल साल 2026 तक बढ़ाया गया

एजेंसी

**नई दिल्ली।** केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 22 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी गोविंद मोहन 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे।एक सरकारी आदेश में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति

समिति (एसीसी) ने 1989 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन की सेवाओं का विस्तार करते हुए उन्हें गृह मंत्रालय में गृह सचिव के रूप में उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 30 सितंबर 2025 से आगे 22?अगस्त?2026 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि गोविंद मोहन ने 23 अगस्त 2024 को गृह सचिव के रूप में जिम्मा संभाला था, जिसके बाद अब उनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले वे संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे और गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव व अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

## अमित शाह ने यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1500 एमजीडी तक बढ़ाने का दिया निर्देश

जेंसी

**नई दिल्ली।** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों को यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता 2028 तक 1500 एमजीडी तक बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने सभी एसटीपी से निकलने वाले पानी की थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया, ताकि जल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

अमित शाह ने गृह मंत्रालय में यमुना नदी के पुनरुद्धार को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा संबंधित मंत्रालयों और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन मोड में काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार को औद्योगिक इकाइयों से

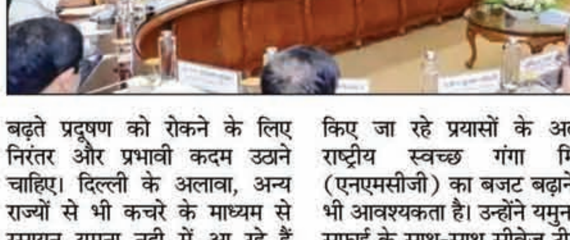

बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निरंतर और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। दिल्ली के अलावा, अन्य राज्यों से भी कचरे के माध्यम से रसायन यमुना नदी में आ रहे हैं इसलिए इन सभी राज्यों को यमुना नदी की सफाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए।अमित शाह ने नजफगढ़ और शाहदरा के मुख्य नालों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) में सुधार के लिए एक्शन मोड पर काम करने पर ज़ोर दिया। अमित शाह ने दिल्ली के दो मुख्य नालों, नजफगढ़ और शाहदरा नालों का ड्रोन सर्वेक्षण कराने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) का बजट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने यमुना की सफाई के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने 2028 तक एसटीपी की क्षमता बढ़ाकर 1500 एमजीडी करने के निर्देश दिए। शाह ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों को यमुना के पुनरुद्धार के लिए प्रयास करने चाहिए ।

## आईपी यूनिवर्सिटी और सीईएमसीए के बीच एमओयू

एजेंसी

**नई दिल्ली।** गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) और कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी को सीईएमसीएआईपीयू नाम दिया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। यह एमओयू सीईएमसीए के निदेशक डॉ. बशीर अहमद शद्रच और जीजीएसआईपीयू के रजिस्ट्रार डॉ. कमल पाठक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। समारोह के दौरान, आईपी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. महेश वर्मा ने इस समझौते को शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा, ÷हम मानते हैं कि शिक्षा सभी के लिए अर्थपूर्ण और सुलभ होनी चाहिए। यह साझेदारी हमारे शैक्षिक समुदाय को उच्च प्रभाव वाली, समावेशी और नवाचारी शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। सीईएमसीए के निदेशक डॉ. बशीर अहमद शद्रच ने अपने वक्तव्य में कहा कि सीईएमसीए मीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा को अधिक न्यायसंगत और सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है।

## तिब्बत के स्कूली बच्चों पर चीन के शोषण को उजागर करती रिपोर्ट जारी

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट ने शोध रिपोर्ट 'जब वे हमारे बच्चों को उठाने आए- चीन के औपनिवेशिक आवासीय विद्यालय और तिब्बत का भविष्य' का हिंदी संस्करण कंस्टीट्यूशन क्लब में जारी कियाा। मूल रूप से अंग्रेजी में इस रिपोर्ट को 28 मई 2025 को ऑनलाइन जारी किया गया है। यह रिपोर्ट चीन सरकार द्वारा तिब्बत के आवासीय विद्यालयों में तिब्बती बच्चों के साथ किए जा रहे शोषण को उजागर करती है। इस लोकार्पण समारोह में प्रमुख भारतीय और तिब्बती नेताओं ने भाग लिया। इनमें राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार, गृह मंत्रालय के पूर्व विशेष सलाहकार अमिताभ माथुर, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक आरके खिरमे, तिब्बत में चीन की आत्मसात और शिक्षा नीतियों के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ. ग्याल लो और तिब्बती सांसद और तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट में एशिया कार्यक्रम प्रबंधक दोरजी सेतेन शामिल रहे। तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट में तिब्बत मामलों और शिक्षा मामलों के विशेषज्ञ डॉ. ग्याल लो ने चीनी की

औपनिवेशिक आवासीय विद्यालय प्रणाली को तिब्बती पहचान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को मिटाने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बताया हैं। उन्होंने कहा कि चीन के औपनिवेशिक आवासीय विद्यालय तिब्बती बच्चों को शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धर्म प्रचारित करने के लिए बनाए गए हैं। इस रिपोर्ट में दिए गए साक्ष्य उनके शोध और उनके अपने परिवार के अनुभव की पुष्टि करते हैं। चीनी अधिकारी जान-बूझकर हमारे बच्चों को हमसे दूर कर रहे हैं और उन्हें अपनी परंपराओं से अलग कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में चीनी सरकार ने तिब्बतियों द्वारा संचालित स्कूलों और स्थानीय गांवों के स्कूलों को बंद किया है, जिससे तिब्बती अभिभावकों के पास अपने बच्चों को सरकारी आवासीय विद्यालयों में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

## दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 थी तीव्रता

एजेंसी

**नई दिल्ली,** ।दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के जिलों में अचानक धरती हिलने लगी, जिससे लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकलकर खुले में आ गए। हालांकि, किसी तरह की क्षति की कोई खबर नहीं आई है।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। भूकंप के झटके शाम 7.49 बजे महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 आंकी गई। इसकी गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी। इससे पहले गुरुवार की सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके आए थे। उसका भी केंद्र झज्जर ही था। दिल्ली-एनसीआर में सुबह दो बार भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 और 3.0 दर्ज की गई थी। भूकंप का केंद्र झज्जर शहर से 10 किलोमीटर उत्तर में था, जिसकी गहराई

जमीन से 10 किलोमीटर नीचे मापी गई थी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली और पूरे एनसीआर में 17 फरवरी को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जो लोग सो रहे थे, उनकी नींद टूट गई, और जो जाग रहे थे, वे दहशत में आ गए। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई जमीन से पांच किलोमीटर नीचे थी जिससे झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं। इस टक्कर के परिणामस्वरूप प्लेट्स के कोने मुड़ सकते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण वे टूट भी सकते हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है और यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है तो भूकंप आता है।

## संपादक की कलम से

# भारत को एक राष्ट्र के रूप में जल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी

डे जीरो–एक ऐसा शब्द है जो अब केवल एक संभावित आपदा नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का प्रतीक बन चुका है। यह शब्द पहली बार 2018 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में तब आया जब दक्षिण अफ्रीका का कैपटाउन शहर पानी की आपूर्ति पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। डे जीरो वह दिन होता है जब शहर के सभी नल बंद कर दिए जाते हैं, और नागरिकों को सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होकर सीमित मात्रा में पानी प्राप्त करना पड़ता है। कैपटाउन में यह सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर निर्धारित की गई थी। हालांकि इस संकट का कारण केवल जलवायु परिवर्तन या वर्षा की अनिश्चितता नहीं था–यह दशकों की नीति विफलता, शहरों का अति-विस्तार, परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा और जल प्रबंधन में बड़ी खामियों का संयुक्त परिणाम था।

कैपटाउन ने कड़ी नीतियों और नागरिक सहभागिता से इस आपदा को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन पानी की गंभीर किल्लत की आहट अब भारत के दरवाजे तक होने लगी है। भारत जैसे देशों में, जहां जनसंख्या अत्यधिक है, शहरीकरण अनियंत्रित है, और भूजल दोहन पर कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं–डे जीरो अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि एक आसन्न यथार्थ है।

बेंगलुरु, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था, आज जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। यहां की अधिकांश झीलें अब या तो कचरा डंपिंग साइट बन चुकी हैं या अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गईं। भूजल स्तर हर वर्ष 10-12 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। बेंगलुरु में डे जीरो की आंशिक झलक तब देखने को मिली जब पूरे शहर में टैंकर के पानी पर निर्भरता बढ़ी।

चेन्नई भी 2019 में डे जीरो जैसे संकट का सामना कर चुका है जब उसके चारों जलाशय सूख गए थे। वहीं दिल्ली की स्थिति भी बेहतर नहीं–शहर की मुख्य जलधारा यमुना प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार है, जबकि भूजल स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में जा चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में जलापूर्ति पूरी तरह समाप्त हो सकती है।

पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति भी चिंताजनक है। धान,गन्ने जैसी अत्यधिक जल-खपत वाली फसलों का विस्तार, सिंचाई तकनीकों का अल्प उपयोग और नगण्य वर्षा जल संचयन ने भूजल अंधाधुंध तरीके से समाप्त कर दिया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार हरियाणा के 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर पार कर चुका है।

भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार केवल वर्षा की अनियमितता नहीं है, बल्कि जल निकायों पर अतिक्रमण, नीति असंगति, शहरी अपशिष्ट का जल स्रोतों में मिलना और लोगों में जल बचत के प्रति उदासीनता जैसे कारक भी उतने ही उत्तरदायी हैं।

जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कागजी आंकड़ों तक ही सीमित रह गया। मसलन, जल जीवन मिशन को सिर्फ हर घर नल तक सीमित समझा गया, जबकि उसका मूल उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों का सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता के जरिए जल आत्मनिर्भरता था।

इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। जल को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर नागरिक सहभागिता पर बल देना होगा। जल संरक्षण को जीवनशैली में लाना होगा झ्र जैसे कैपटाउन में लोगों ने बर्तनों में नहाने का पानी जमा कर पौधों को सींचा, हाथ धोते समय नल बंद करना सीखा और शौचालयों में रिसाइकल पानी का प्रयोग शुरू किया।

भारत में भी प्रत्येक इमारत में वर्षा जल संचयन अनिवार्य करना चाहिए, जिसे स्थानीय निकाय सख्ती से लागू करें। भूजल का मापन, नियमन और पुनर्भरण एक समर्पित मिशन के तहत चलाया जाए। जल जीवन मिशन को स्थानीय स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण पर केंद्रित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट की जगह परकोलेशन पिट्स, बायोस्वेल्स और हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे ताकि वर्षा जल भूमि में जज्ब हो सके। पानी की कीमत समझना और उपभोग पर नियंत्रण लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्लैब आधारित मूल्य निर्धारण, जहां न्यूनतम जरूरतों के बाद अतिरिक्त खपत पर उच्च शुल्क लगे, एक व्यावहारिक नीति हो सकती है। इससे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग प्रोत्साहित होगा। वहीं, तकनीकी नवाचार जैसे जल रिसाव की स्मार्ट निगरानी, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और समुद्री जल से मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया को प्रमुखता दी जानी चाहिए। चेन्नई ने समुद्री जल शोधन संयंत्र की ओर कदम बढ़ाया है, और यह उन तटीय शहरों के लिए प्रेरणा हो सकता है जहां भूजल या वर्षा जल अपर्याप्त है।

# मराठी बोलना गर्व की बात, लेकिन हिन्दी से घृणा क्यों ?

अजय जैन विकल्प

अपनी स्थापना से ही भारत विविधताओं का देश बना हुआ है और भाषा इसकी सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। इसलिए यहाँ अनेकता के बावजूद एकता है, चाहे फिर कोई भी मुद्दा हो, यानी कभी अपने को श्रेष्ठ बताकर किसी अन्य को बुरा नहीं कहा गया, किन्तु इस देश के राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में फिलहाल यही बुरा देखा जा रहा है, जो अनुचित है और देश की भाषाई एकता के लिए घातक भी है।

मुम्बई न केवल आर्थिक राजधानी है, बल्कि भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का संगम स्थल भी है। इस महानगर में मराठी का बोलबाला होना स्वाभाविक है, यह इस मिट्टी की आत्मा है, लेकिन आज एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है:हिन्दी के प्रति अघोषित घृणा दिख रही है, जिसके पीछे असहिष्णुता, राजनीतिक विद्वेष एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने की अजीब मानसिकता है। मराठी को सम्मान देने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपत्ति तब होती है, जब इस सम्मान के नाम पर हिन्दी को हाशिए पर धकेला जाता है, हिन्दी भाषियों को बाहरी करार दिया जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह केवल भाषाई टकराव नहीं, एक गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसे समझना, उजागर करना और विरोध करते हुए हिन्दी के लिए खड़े रहना बहुत आवश्यक है। यह समझना होगा कि मराठी स्वाभिमान की भाषा है, लेकिन हिन्दी के प्रति संकीर्णता सही नहीं है। मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि सभ्यता, इतिहास और गौरव है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक आदि महापुरुषों ने मराठी को जनचेतना और क्रांति का माध्यम बनाया, तो कैद में रहते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए वीर विनायक सावरकर ने हिन्दी कविताएं रचीं एवं हिन्दी सिखाई। आज भी महाराष्ट्र में मराठी साहित्य, नाटक, संगीत और संस्कृति की धारा बह रही है।

मराठी बोलना, मराठी में गर्व करना, उस विरासत को आगे बढ़ाना हर मराठीभाषी का हक और कर्तव्य है मगर जब यह गर्व दूसरों की भाषा के प्रति घृणा में बदल जाता है, तो यह स्वाभिमान नहीं, संकीर्णता बन जाता है।

सबको समझना पड़ेगा कि हिन्दी एकता का सेतु और मुम्बई का मौन आधार है। हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने-कोने तक संवाद का माध्यम है। मुम्बई जैसे महानगर में हिन्दी केवल उत्तर भारतीयों की नहीं, बल्कि लाखों मराठी, गुजराती, बिहारी, तमिल, मलयाली और बंगालियों के भी दैनिक संवाद की भाषा बनी हुई है।

मुम्बई यानी बॉलीवुड सहित रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन, सेवा क्षेत्र और मीडिया के अधिकतर प्रमुख उद्योग हिन्दी के दम पर खड़े हैं। यही नहीं, लाखों मेहनतकश मजदूर, वाहन चालक, नौकर, घरेलू कामगार, उद्घोषक, पत्रकार और कलाकार भी हिन्दी के माध्यम से ही रोजी-रोटी व पहचान प्राप्त करते हैं, तो बड़ा सवाल है कि इस हिन्दी से इतनी घृणा क्यों, मारपीट क्यों, प्रदर्शन क्यों...?

स्थानीय राजनीतिक कारण देखें तो पता चलता है कि मराठी बनाम हिन्दी की कृत्रिम खाई बनाई गई है, क्योंकि उसी से तो सत्ता प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। भाषा का यह संघर्ष अचानक नहीं पनपा है, बल्कि यह कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम है। मराठी मानुस के नारे के पीछे वर्षों से एक अपराध-बोध और भय को बोया गया, कि हिन्दी भाषी मुम्बई को हड़प रहे हैं, जबकि सत्यता इससे अलग है और धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिन्दी बोलने वाला अपना काम कर रहा है, तो मराठी एवं अन्य भाषा बोलने वाला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। राज्य और मुम्बई को निगलने के ऐसे विचार न केवल झूठे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हैं, क्योंकि मुम्बई की आत्मा में तो हिन्दी हमेशा रही है। १९५० के दशक में भी जब बम्बई राज्य बना था, तब भी हिन्दीभाषी इसके विकास में बराबरी से सहभागी थे।

हिन्दी को बाहरी भाषा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि संविधान में यह राजभाषा घोषित है और इसे पूरे भारत में समान सम्मान प्राप्त है। ऐसा भी लगता है कि असल डर हिन्दी से नहीं, बल्कि उस जनसांख्यिकी बदलाव से है, जो उत्तर भारत से आए श्रमिकों और युवाओं के कारण मुम्बई में हो रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा में गिरावट और स्थानीय युवाओं को नौकरियों नहीं मिलने का दोष भी हिन्दी भाषियों पर डाल देना आसान बहाना बन गया है, लेकिन इसका उचित समाधान खोजने की अपेक्षा हिन्दी को रोककर गुंडागर्दी करना कहाँ से सही हो गया है ? क्या हिन्दी भाषियों को निकाल देने से, हिन्दी नहीं बोलने देने से, राजनीति करने से एवं सिर्फ मराठी की जिद लगाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा ? राज्य तरक्की कर लेगा, हिन्दी और मराठी का स्नेह बना रहेगा ?

उत्तर साफ है-नहीं, क्योंकि विकास की कुंजी भाषाओं को सीमित करने में नहीं, बल्कि उन्हें सर्वव्यापी व समावेशी बनाने में है। राजनीति के चक्कर में यह भूलना घातक है कि हिन्दी को अपमानित करना आसान है। वास्तव में यह संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान की धारा ३४३ हिन्दी को राजभाषा घोषित करती है। अनुच्छेद १९ हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो कोई भी राज्य, नगर या संस्था किसी भाषा विशेष को किसी को बोलने से कैसे रोक सकता है। मुम्बई में हिन्दी बोलने वाले पर तंज कसना, दुकानों के बोर्ड बदलवाना या हिन्दी में सेवा देने से इनकार करना सीधे तौर पर संविधान का सीधा उल्लंघन यानी राष्ट्रद्रोह है।

मुम्बई में हिन्दी का विरोध करने वालों एवं भाषा के बँटवारे पर मौन रहने वालों को भाषाई सौहार्द के उदाहरण दक्षिण भारत से सीख लेनी चाहिए। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी भाषाओं को मजबूत किया, लेकिन कभी हिन्दी को दुश्मन नहीं बनाया। बेंगलुरु जैसे शहर में भी कन्नड़ प्रमुख है, लेकिन हिन्दी स्वीकार है। वहाँ के लोग हिन्दी सीखते हैं, सिखाते हैं और साथ रहते हैं।

मुम्बई, जो देश का सबसे बड़ा समावेशी शहर कहलाता है, वहाँ से हिन्दी फिल्म और टी.वी. उद्योग निकाल दिया जाए, तो कल्पना करें कि क्या बचेगा ? अगर हिन्दी बोलने वाला अपने ही देश में पराया महसूस करे, तो यह केवल शर्मनाक नहीं, बड़ा जहर है।

सबको इस बात को महसूस करना होगा कि भाषाई टकराव से कुछ नहीं सधेगा। मराठी और हिन्दी दोनों समृद्ध भाषाएं हैं। दोनों में साहित्य, संस्कृति, ज्ञान और इतिहास की गहराइयाँ हैं। इसलिए कुछ सकारात्मक कदम एवं उदारता लेकर विद्यालयों में मराठी और हिन्दी दोनों को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सार्वजनिक बोर्डों में मराठी प्रमुख हो, लेकिन हिन्दी को न हटाया जाए। सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाए, जो भाषाई सौहार्द को बढ़ावा दें। यानी नेता वोट बैंक के लिए भाषा को हथियार न बनाएं।

राजनीति से पनपाए गए इस विवाद का समाधान बनाम निष्कर्ष यही है कि मुम्बई की आत्मा मराठी और हिन्दी का संगम है, यानी मुम्बई केवल मराठी या हिन्दी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। जैसे कश्मीर भारत का स्वर्ग है, ऐसे ही महाराष्ट्र और मुम्बई का असली सौंदर्य विविधता-अनेकता में है। हिन्दी से घृणा करके हम न तो मराठी को मजबूत कर सकते हैं, न मुम्बई को।

मराठी और हिन्दी २ भाषाएं नहीं, २ आत्माएं हैं-जिन्हें जोड़कर ही भारत एकता और शक्ति की मिसाल बनेगा। कारण कि किसी भी भाषा से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा से घृणा करना अपने ही देश और उसके नियम-कायदों से घृणा करने जैसा है।

यह भी तय है कि मुम्बई और राज्य के अन्य हिस्सों में मराठी बनाम गैर-मराठी भाषा विवाद को लेकर चल रहे राजनीतिक और सामाजिक तनाव, प्रदर्शन, गुंडागर्दी और जबरदस्ती से भाषा एवं क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा हल नहीं होगा, बल्कि इससे आमजन के बीच विश्वास घटकर विष फैलेगा। बेहतर यह है कि सरकार और सभी को राज्य-देश हित में इस घमासान को टालते हुए देशप्रेम दिखाकर दोनों भाषा का सम्मान स्वीकारना चाहिए।

# सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

भारत में मुख्यधारा का मीडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह मानते हुए अब सकारात्मक रवैया अपनाने लगा है, खासकर तब, जबकि इसमें किसी भी तरह भाजपा का हित जुड़ा हो। प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली में कॉलेज छात्रों को दिए एक भाषण में अपनी सकारात्मक सोच का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि वे गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, इस सवाल पर कहते हैं कि गिलास पूरा भरा है, जो खाली दिख रहा है, वहां हवा भरी है। तो बस तब से देश में ऐसे ही हवा-हवाई माहौल चल रहा है। कुछ रहे न रहे, बस सब चंगा सी की उम्मीद पर देश को चलाया जा रहा है। मीडिया भी तथ्यों को न देखकर हवा-हवाई बातों को बढ़ा रहा है। जैसे गुरुवार को मीडिया ने इस बात को जोर-शोर से चलाया कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की कवायद पर शीर्ष अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन ये हवा से आधे भरे गिलास का उदाहरण है। असल बात ये है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि वह जिन 11 दस्तावेज की मांग मतदाताओं से कर रहा है, उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं, यह गृहमंत्रालय का विषय है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर

ही सुनवाई होने दी और उसकी अहम टिप्पणियां भी इन्हीं के आधार पर थीं। सुप्रीम कोर्ट न पूरी तरह चुनाव आयोग के पक्ष में दिखा, न उसने याचिकाकताओं की तरफ कोई पक्षपात दिखाया, बल्कि उसकी तटस्थता साफ नजर आई, फिर भी मीडिया में चलाए जा रहे शीर्षक यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बिहार में जिस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को विपक्ष ने इतना बड़ा हल्ला बोल किया, उस मुद्दे पर विपक्ष को अदालत में झटका मिला है। जबकि ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की कवायद शुरू की और इसके लिए केवल एक महीने का ही वक्त मतदाताओं को दिया कि वे अपने नागरिक होने का प्रमाण खुद ही पेश करें। आयोग ने 11 दस्तावेज की सूची जारी की और कहा कि इनमें से किसी को पेश करने पर ही किसी का नाम मतदाता सूची में आएगा, अन्यथा काट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं से खुद के नागरिक होने का सबूत मांगा, जबकि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दी, जबकि करोड़ों गरीबों के पास यही सबसे सुलभ पहचानपत्र होते हैं और इन्हें भी सरकार ही जारी करती है। इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला करते हुए चुनाव आयोग के समक्ष विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया था, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद करवाया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अलावा राजद सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल, राकांपा (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी. राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद, और भाकपा (माले) के दीपंकर भट्टाचार्य, इन सभी ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष गहन पुनरीक्षण में कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगभग 7.9 करोड़ नागरिकों को कवर करेगी, और इसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है जबकि यह काम चुनाव आयोग का है।

उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। इस मामले में गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तब जस्टिस धूलिया ने कहा, लेकिन नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग को अनुच्छेद 326 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। वहीं जस्टिस बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए, तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंततः आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर सकते हैं ताकि गैर-नागरिक सूची में न रहें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य प्रस्तावित चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन आयोग को तीन दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का सुझाव दिया है।

# सांप: रहस्य नहीं, समझ का विषय हैं वे

सांपों को लेकर मानव समाज में आदिकाल से ही रहस्य, भय और अंधविश्वास जुड़ते चले आए हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में सांप केवल एक जीव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रतीकों से जुड़ा हुआ नाम है। नाग देवता की पूजा से लेकर लोक कथाओं, परंपराओं और फिल्मों तक, सांप को कभी आराध्य रूप में तो कभी खलनायक के रूप में देखा गया है। लेकिन इस भावनात्मक और काल्पनिक दृष्टिकोण से अलग, अगर हम सांपों को वास्तविकता और वैज्ञानिक समझ के साथ देखें, तो एक बिलकुल अलग तस्वीर सामने आती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें सांप न भयावह हैं, न रहस्यमयी, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत और आवश्यक रचना हैं।

धरती पर सांपों की लगभग 3,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में करीब 300 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से भी केवल कुछ ही प्रजातियाँ विषैली होती हैं, जैसे कि कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जिन्हें बिग फोर कहा जाता है। शेष अधिकांश सांप निरपराध और मानव के संपर्क से बचने वाले जीव हैं। लेकिन डर और अज्ञानता के चलते अक्सर हर सांप को खतरनाक समझा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, चाहे वह विषैला हो या नहीं। वास्तव में, सांप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। वे खेतों और घरों में चूहों व अन्य कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जो फसलों और खाद्यान्न को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि सांप न हों, तो यह असंतुलन खाद्य श्रृंखला में भारी विघटन ला सकता है। उनके बिना हमारी जैव विविधता अधूरी है। सांपों का शरीर बिना पैरों के होते हुए भी अत्यंत लचीला, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होता है। वे जंगलों, खेतों, रेगिस्तानों, पर्वतों और यहाँ तक कि बफीर्ले इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं। उनकी खाल समय-समय पर झड़ती है, जिसे कुछ परंपराओं में नवजीवन या पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में शेषनाग, वासुकी और अनंत जैसे नागों की कथाएँ आज भी जीवंत हैं। भगवान विष्णु के शयन के आसन से लेकर शिव के गले में लिपटे वासुकी तक, सांपों को ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। नागपंचमी जैसे पर्व, नाग मंदिरों की स्थापना और नाग-कथाओं की समृद्ध परंपरा इस सांप-मानव संबंध को एक पवित्र आयाम देती हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह आवश्यक हो गया है कि हम सांपों को केवल पौराणिक या रहस्यमयी दृष्टि से नहीं, बल्कि विवेक और तथ्य की दृष्टि से भी समझें।

दुर्भाग्यवश, हिंदी फिल्मों, लोक कथाओं और टेलीविजन धारावाहिकों ने सांप को प्रतिशोध लेने वाले जीव के रूप में चित्रित किया है। कहा जाता है कि साँप अपनी मादा की हत्या का बदला लेते हैं, किसी की तस्वीर अपनी आँखों में कैद कर लेते हैं और वर्षों बाद भी शत्रु को पहचान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि साँप न तो इंसान को शिकार मानते हैं, न ही उन्हें कोई प्रतिशोध भाव होता है। वे केवल तभी काटते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। यानी, काटना उनका रक्षात्मक व्यवहार है, आक्रामक नहीं।

अब समय आ गया है कि हम सांपों के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएँ। देश में कई संस्थाएँ कार्यरत हैं जो सांपों की पहचान, संरक्षण और जन-जागरूकता के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाना बेहद आवश्यक है कि कौन से सांप विषैले होते हैं, उनके काटने पर क्या करना चाहिए, और किस प्रकार हमें उनसे डरने के बजाय समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। जब ज्ञान भय का स्थान लेगा, तभी सह-अस्तित्व की भावना उत्पन्न होगी।

# मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

**–ललित गर्ग–**

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

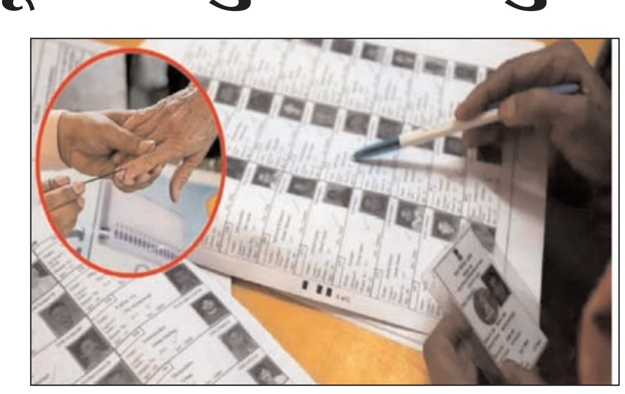

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि जो सरकार करे, उसका विरोध करो, चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ?

क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है।

भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है।

बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं।

## इमरान खान के बेटों पर भी आफतः सत्ताधारी पार्टी ने दी कड़ी वॉर्निंग, कहा- 'देश में आकर अदालत का सामना करें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी'

**एजेंसी**

**इस्लामाबाद।** पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, और अब इसका असर उनके परिवार पर भी दिख रहा है। सत्ताधारी पार्टी ने इमरान खान के बेटों, कासिम खान और सुलेमान खान को कड़ी वॉर्निंग देते हुए कहा है कि वे देश में आकर अदालत का सामना करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इमरान खान खुद कई गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। सत्ताधारी गठबंधन के एक प्रमुख नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान के बेटों को कथित देश विरोधी गतिविधियों और सरकार के खिलाफ मानहानि वाले बयानों के संबंध में चल रहे मामलों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कासिम और सुलेमान, जो लंदन में रहते हैं, स्वेच्छा से पाकिस्तान नहीं लौटते और अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होते, तो उनके खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी करने सहित सभी कानूनी विकल्प तलाशे जाएंगे। यह कदम इमरान खान के समर्थकों और उनके परिवार पर दबाव बनाने की एक और कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि सरकार उनके राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चेतावनी केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि इमरान खान पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी है।

## अदालत ने दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में बिना उचित कारण आव्रजन गिरफ्तारियां रोकने का दिया आदेश

**वाशिंगटन।** अमेरिका की एक संघीय अदालत ने पाया कि गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) लॉस एंजिल्स में आव्रजन छापेमारी के दौरान बिना किसी संभावित कारण के लोगों को रोक रहा है और गिरफ्तारियां कर रहा है तथा विभाग को आदेश दिया कि वह केवल नस्ल, भाषा या व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों को हिरासत में लेना बंद करे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश मैम इवुसी-मेन्सा फ्रिम्पोंग ने आदेश दिया कि डीएचएस को अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन विकसित करना चाहिए ताकि वे उचित संदेह का निर्धारण कर सकें। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले सप्ताह दक्षिणी कैलिफोर्निया के एसीएलयू ने पांच लोगों और आव्रजन वकालत समूहों की ओर से ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डीएचएस ने असंवैधानिक गिरफ्तारियां की हैं।न्यायाधीश फ्रिम्पोंग ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासन यह जानकारी देने में विफल रहा कि किस आधार पर उन्होंने गिरफ्तारियां कीं। न्यायाधीश ने डीएचएस को गिरफ्तारी का दस्तावेज बनाने और याचिकाकर्ताओं के वकीलों को प्रदान करने का भी आदेश दिया।

## अमेरिकी विदेश विभाग में 1,000 से अधिक लोगों की छंटनी

**वाशिंगटन।** ट्रम्प प्रशासन द्वारा संघीय कार्यबल में कटौती के प्रयासों के अंतर्गत अमेरिकी विदेश विभाग के 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह जानकारी शनिवार को बीबीसी ने एक रिपोर्ट में दी। विदेश विभाग के कर्मचारियों को भेजे गए नोटिस के अनुसार अनैच्छिक कर्मचारी कटौती में 1,107 सिविल सेवा और 246 विदेश सेवा के कर्मचारी शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत में संघीय सरकार के विशाल पुनर्गठन प्रयास के अंतर्गत 1,500 से अधिक विदेश विभाग के कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दिया था। आलोचकों का कहना है कि ये बड़ी कटौती विभाग के काम पर असर डालेंगी। सीबीएस न्यूज के अनुसार, जनसंख्या, शरणार्थी और प्रवासन ब्यूरो में लगभग सभी सिविल सेवा अधिकारियों की छंटनी कर दी गई है। जिन व्यक्तियों को नौकरी से निकाला गया उनमें विदेश विभाग के अफगान पुनर्वास प्रयासों के समन्वयक (केयर) कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल हैं। सीनेट की विदेश संबंध समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने एक बयान जारी कर कहा कि विदेश विभाग में सिविल सेवा और विदेश सेवा के सैकड़ों सदस्यों को निकालने का निर्णय हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है।

## दक्षिणी गाजा में इज़रायली कमांडर की मौत

**यरूशलम।** दक्षिणी गाजा पट्टी में एक घटना में इजायल के एक लड़ाकू कमांडिंग अधिकारी की मौत हो गई। इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक बयान में यह जानकारी दी। रीई बिरान (21) आईडीएफ की गोलानी टोही इकाई में एक स्क्वाड कमांडर थे। इज़रायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने बताया कि खान यूनिस में सक्रिय गोलानी बल ने एक ऐसी इमारत में प्रवेश किया जिसके आतंकवादी ढाँचा होने का संदेह था। जब सैनिक इमारत में बारूदी सुरंगें बना रहे थे, तभी एक विस्फोट हुआ, जिसमें कमांडर की मौत हो गई। बाद में शुक्रवार को, आईडीएफ ने एक अलग बयान में कहा कि उसके बख्तरबंद बलों ने इज़रायली वायु सेना के साथ मिलकर एक सशस्त्र दस्ते को मार गिराया जो उनके पास आया था और खान यूनिस क्षेत्र में खतरा पैदा कर रहा था। इसमें आगे कहा गया है कि बख्तरबंद बलों ने ज़मीन के ऊपर और नीचे, दोनों जगहआतंकवादी ढाँचे को ध्वस्त कर दिया और हथियार और सैन्य उपकरण ज़ब्त कर लिए।

## 1 अगस्त की समय सीमा से पहले देश टैरिफ वार्ता के लिए कड़ी मेहनत करते रहें : डोनाल्ड ट्रंप

**एजेंसी**

**वाशिंगटन ।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन के साथ चल रही व्यापार वार्ता में शामिल देशों को 1 अगस्त की वार्ता की समयसीमा से पहले कड़ी मेहनत करते रहने की सलाह दी है। उन्होंने अपना यह दावा भी दोहराया है कि दोस्त और दुश्मन दोनों ने अमेरिका का कई वर्षों से फायदा उठाया है। ट्रंप ने यह टिप्पणी टेक्सास के बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए रवाना होने से पहले की। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य देश 1 अगस्त से लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव से बचने या उसे कम करने के लिए अमेरिका के साथ समझौते करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। आप जानते हैं, कई वर्षों से दोस्त और दुश्मन, दोनों देशों ने हमारा फायदा उठाया है और सच कहूं तो कई

मामलों में दोस्त दुश्मनों से भी बदतर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं कहूंगा, बस मेहनत करते रहो। सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका 1 अगस्त से दक्षिण कोरियाई उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाना शुरू करेगा। उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं के लिए व्यापार बाधाओं को दूर करने, अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिकी विनिर्माण के पुनर्निर्माण के अभियान के तहत अप्रैल में नई टैरिफ योजना की घोषणा की थी। इस बीच, दोनों पक्षों ने कहा कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सप्ताह सोल में द्विपक्षीय गठबंधन को पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से आधुनिक बनाने और इसे भविष्य-उन्मुख और व्यापक रणनीतिक गठबंधन के रूप में मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यह परामर्श ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन सहयोगियों और साझेदारों से अपने बोझ साझाकरण को मजबूत करने का आह्वान कर रहा है, साथ ही तेजी से आक्रामक होते चीन से बढ़ते खतरे को रोकने को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, दोनों पक्षों ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन को भविष्योन्मुखी, व्यापक रणनीतिक गठबंधन के रूप में मजबूत करने और उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश में पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से गठबंधन का आधुनिकीकरण करने के तरीकों पर चर्चा की।

## ताइवान के आसपास चीन ने सैन्य हलचल तेज की, नौ विमान एडीआईजेड में घुसे

**एजेंसी**

**ताइपे (ताइवान)।** चीन ने एकबार फिर ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक ताइवान के आसपास चीन के 14 सैन्य विमानों, नौ नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज की गतिविधियों का पता लगाया। इन 14 सैन्य विमानों में से नौ तो मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश भी किया।

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर यह विवरण साझा किया है। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के सशस्त्र बल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। साथ ही सैन्य विमान, नौसैनिक जहाज और तटीय मिसाइल प्रणालियां तैनात कीं। ताइपे टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, चीन अपने जहाजों के माध्यम से ताइवान इलाके में गुआम के आसपास समुद्री तल का मानचित्रण कर रहा है। इससे उसे समुद्र के नीचे केबल बिछाने में मदद मिल सकती है और वह इसका सैन्य उपयोग भी कर सकता है।

## अफ्रीका में हैजा और एमपॉक्स का प्रकोप, इस साल 4,200 से ज्यादा की मौत

**एजेंसी**

**अदीस अबाबा ।** अफ्रीका में 2025 में हैजा और एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) जैसी बीमारियों के कारण अब तक 4,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) ने दी है। एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अफ्रीका सीडीसी में एमपॉक्स के डिप्टी इन्सिडेंट मैनेजर, याप बूम द्वितीय ने बताया कि हैजा और एमपॉक्स को इस साल की सबसे बड़ी बीमारी माना जा रहा है, जिसकी वजह से कुल 4,275 लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकी संघ की एक खास स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, इस साल की शुरुआत से अब तक अफ्रीका के 21 देशों में लगभग 1,76,136 लोग हैजा से बीमार हुए हैं, और 3,697 लोगों की मौतें हुई हैं। अफ्रीका में बार-बार हैजा फैलने की सबसे बड़ी वजह साफ पानी की कमी है। इसके अलावा, अफ्रीका की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनकी स्थिति और दयनीय हो गई

है। अफ्रीका सीडीसी के अनुसार, 2025 की शुरुआत से अब तक, अफ्रीका के 23 देशों में एमपॉक्स के 79,024 मामले सामने आए हैं और 578 लोगों की जान इस बीमारी से जा चुकी है। पिछले साल अगस्त में, अफ्रीका सीडीसी ने एमपॉक्स को महाद्वीपीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था। इसके कुछ समय बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी एमपॉक्स को जन स्वास्थ्य आपातकाल स्थिति बताया। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, हैजा गंदा पानी पीने या संक्रमित खाना खाने से होता है। यह बीमारी विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। हैजा को दुनियाभर में एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा माना गया है। इससे बचाव के लिए साफ पानी, शौचालय और अच्छी सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है।

## ट्रंप प्रशासन को जज का आदेश, लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया में आव्रजन छापे फौरन रोके जाएं

**एजेंसी**

**लॉस एंजिल्स।** संघीय न्यायाधीश मामे इवुसी-मेन्सा फ्रिम्पोंग ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के नागरिक अधिकार मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया। संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को तत्काल लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया के कई अन्य काउंटियों में आव्रजन छापों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। छापे की यह कार्रवाई कई दिनों से संयुक्त राज्य अमेरिका आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) कर रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इन छापों को तत्काल रोका जाए। सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, जिला न्यायाधीश फ्रिम्पोंग ने फैसले में लिखा, आईसीई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौथे संशोधन का उल्लंघन कर रहा है। न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि संघीय एजेंट बिना पुख्ता साक्ष्य के धरपकड़ नहीं कर सकते। एसीएलयू और आप्रवासी अधिकार समूहों ने कानूनी दस्तावेज में दावा किया कि संघीय एजेंट रंगभेद के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना वारंट के छापा मार रहे हैं। लोगों को कानूनी सलाह नहीं लेने देते। संघीय एजेंट खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। एसीएलयू के वकील मोहम्मद ताजसर ने कहा, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, वे कोई भी भाषा बोलते हों या कहीं भी काम करते हों, सभी को गैरकानूनी रोक से बचाने के लिए संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने मुकदमे के दौरान इन दावों का खंडन किया। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि संघीय सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं। अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसेली ने फैसले के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि संघीय एजेंट कानून लागू करते रहेंगे और अमेरिकी संविधान का पालन करेंगे। हम मुकदमे में लगाए गए आरोपों से पूरी तरह असहमत हैं। हम यह मानते हैं कि एजेंटों ने कभी भी बिना उचित कानूनी औचित्य के किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया। इस फैसले पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा, आज न्याय की जीत हुई। अदालत के फैसले से संघीय आव्रजन अधिकारियों के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने और नस्लीय भेदभाव करने पर अस्थायी रोक लग गई है। बताया गया है कि संघीय जज फ्रिम्पोंग ने दो अस्थायी निरोधक आदेश जारी किए हैं। सनद रहे, जज फ्रिम्पोंग की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने की थी। फ्रिम्पोंग ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की है। फ्रिम्पोंग ने फैसले में लिखा, बिना किसी संदेह के गश्ती दल का घूमना संविधान के चौथे संशोधन का उल्लंघन है और वकीलों को पहुंच से वंचित करना संविधान के पांचवें संशोधन का उल्लंघन है।

## विदेश मंत्रियों की बैठक में उत्तर कोरिया-रूस ने माना- 'हमारे संबंध मजबूत'

**एजेंसी**

**रूस ।** रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार, उत्तर कोरिया और रूस ने शनिवार को उत्तर कोरिया के एक तटीय रिसॉर्ट शहर में शीर्ष राजनयिकों की बैठक के दौरान अपने मजबूत संबंधों को फिर से दोहराया है। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' के अनुसार, उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन-हुई ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से वॉनसान शहर में मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता के दूसरे दौर के तहत हुई। लावरोव एक दिन पहले ही उस शहर में पहुंचे थे, जहां इस महीने की शुरुआत में एक नया पर्यटक क्षेत्र खोला गया है। सर्गेई लावरोव ने चोई सोन-हुई के द्विपक्षीय संबंधों को अजेय सैन्य भाईचारा बताया। उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी क्षेत्र कुर्स्क में यूक्रेनी बलों के

खिलाफ रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। तास की रिपोर्ट के अनुसार, लावरोव ने यह भी वादा किया है कि वह इस तटीय शहर में अधिक रूसी पर्यटकों को लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यहां फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। चोई ने रूस के प्रति अपने देश के समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके संबंध अटूट हैं। तास ने चोई के हवाले से कहा, डीपीआरके (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया) सरकार का रणनीतिक निर्णय और उनकी इच्छा रूस की राज्य संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की नीति का बिना शर्त और निरंतर समर्थन करना है। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, लावरोव का उत्तर कोरिया दौरा रविवार तक चलेगा, जिसके बाद वह चीन रवाना होंगे, जहां वह शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। लावरोव की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सहयोग व्यापक हो रहा है। यह प्रक्रिया तब से तेज हुई है, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई राजनेता किम जोंग-उन ने जून 2024 में प्योंगयांग में हुई शिखर बैठक के दौरान एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

## पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को श्री 5 महाराजधिराज लिखने के कारण संवाद सचिव हिरासत में

**एजेंसी**

**काठमांडू।** पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के नाम पर वक्तव्य जारी करते समय उनके नाम के आगे श्री 5 महाराजधिराज लिखने के कारण उनके संवाद सचिव फणीराज पाठक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की इस कार्यवाही पर राजा समर्थक दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आपत्ति जताई है। काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता एसपी अपील राज बोहरा ने

बताया कि संविधान के विपरीत आचरण करने के आरोप में पूर्व राजा के संवाद सचिव फणीराज पाठक को हिरासत में लिया गया है। एसपी बोहरा ने बताया कि पूर्व राजा के नाम पर जारी वक्तव्य में या सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके नाम के आगे राजतंत्र की शैली में श्री 5 महाराजधिराज का संबोधन किया जा रहा है। इस बात को लेकर संसद में कई सांसदों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

## ब्राजील का राष्ट्रपति कार्यालय अमेरिका से आने वाले 'बोल्सोनारो इफैक्ट टैरिफ' को रिसीव नहीं करेगा

**एजेंसी**

**ब्रासीलिया/वाशिंगटन।** ब्राजील का राष्ट्रपति कार्यालय अमेरिका से भौतक रूप से आने वाले डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत वाले पत्र 'बोल्सोनारो इफैक्ट टैरिफ' को रिसीव नहीं करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अपने राजनयिकों को इस आशय का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम से ब्राजील के राष्ट्रपति भड़के हुए हैं। अमेरिका के सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने आरोप लगाया कि ट्रंप की ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मित्रता है। इसलिए वह जेयर के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खत्म करने का दबाव बनाने के लिए आयात करों में 50 फीसद की वृद्धि करने के वादे पर आमादा हैं। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यह टैरिफ ब्राजील पर लगाते हैं तो वह अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाएंगे। लूला ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत विफल हो जाती है, तो वे इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से मंजूर किए गए ब्राजील के पारस्परिकता कानून को लागू कर देंगे। सीबीएस का मानना है कि लूला की टिप्पणियों से दोनों देशों के बीच टैरिफ युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कि ट्रंप की जिद है कि अगर कोई देश अपने टैरिफ लगाकर अमेरिका को दंडित करने की कोशिश करेगा, तो वह इसका कड़ा जवाब देंगे। इस घटनाक्रम के बाद लूला के आलोचक भी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। ब्राजील सीनेट के अध्यक्ष सीनेटर डेवी अल्कोलुम्ब्रे और चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष ह्यूगो मोट्टा ने कहा कि पारस्परिकता कानून लागू करना ही बेहतर विकल्प है। ब्राजील की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। दोनों ने संयुक्त बयान में कहा, हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने उत्पादक क्षेत्र और ब्राजीलियाई नौकरियों की सुरक्षा के लिए संतुलन और दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति का मानना है कि ट्रंप बोल्सोनारो के आपराधिक मुकदमे के नतीजे को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने 2022 में चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए ट्रंप जैसा काम किया। उधर, बोल्सोनारो का कहना है कि ब्राजील का सर्वोच्च न्यायालय उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। साओ पाउलो स्थित इंस्पर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कार्लोस मेलो का मानना है कि बोल्सोनारो के मुकदमे के बारे में लूला या ब्राजील कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई भी बदलाव ब्राजील के लिए आत्मसमर्पण जैसा होगा। इस बीच लूला ने अपने राजनयिकों को आदेश दिया कि अगर ट्रंप का पत्र ब्रासीलिया स्थित राष्ट्रपति भवन में भौतिक रूप से पहुंचता है, तो उसे वापस कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।

## चीन का तियानझोउ-9 मालवाहक यान पहुंचाया गया प्रक्षेपण स्थल पर

**एजेंसी**

**वेनचांग।** चीन के अंतरिक्ष स्टेशन तक सामग्री पहुंचाने वाले तियानझोउ-9 मालवाहक यान और लॉन्ग मार्च-7 वाहक रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल पर स्थानांतरित किया गया। यह जानकारी चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी (सीएमएसए) ने दी। सीएमएसए के अनुसार मालवाहक अंतरिक्ष यान को निकट भविष्य में उचित समय पर प्रक्षेपित किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि वर्तमान में दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल पर सुविधाएं और उपकरण अच्छी स्थिति में हैं। प्रक्षेपण से पहले व्यापक कार्यक्षमता जांच और संयुक्त परीक्षण योजना के अनुसार किए जाएंगे।

तियानझोउ-9 एक मानवरहित कार्गो अंतरिक्ष यान है, जिसे चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को फिर से आपूर्ति करने के लिए विकसित किया

गया है। यह यान चीन के हैनान प्रांत में स्थित वेनचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रसद, उपकरण और वैज्ञानिक प्रयोगों को पहुंचाना है। यह यान अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करेगा और कार्गो को स्टेशन में स्थानांतरित करेगा। यह मिशन चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को लगातार चालू रखने और वैज्ञानिक अनुसंधान को जारी रखने में मदद करेगा।

## 120 मौतों के बाद टेक्सास में हुई बाढ़ से तबाही का जायजा लेने जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप

**ऑस्टिन।** टेक्सास में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज टेक्सास का दौरा करेंगे ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का व्यक्तिगत रूप से जायजा ले सकें। उनके इस दौरे का उद्देश्य प्रभावितों को सांत्वना देना और संघीय सहायता की आवश्यकताओं का आकलन करना है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप आज सुबह टेक्सास के लिए उड़ान भरेंगे। वे सबसे पहले राज्य के कुछ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे, ताकि नुकसान की व्यापकता को करीब से समझ सकें। इसके बाद, उनके जमीन पर उतरकर स्थानीय अधिकारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों और बाढ़ पीड़ितों से मिलने की उम्मीद है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब टेक्सास रिकॉर्ड तोड़ बारिश और नदियों के उफान के कारण अपने सबसे बुरे प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। कई शहरों में बाढ़ का पानी घरों और व्यवसायों में घुस गया है, जिससे व्यापक विनाश हुआ है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह दौरा संघीय सरकार की ओर से टेक्सास को दी जाने वाली सहायता के दायरे और प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।

## छात्र सोहाग की हत्या से ढाका में भड़का जन-आक्रोश, बीएनपी कार्यकर्ताओं पर लिंचिंग का आरोप

**एजेंसी**

**ढाका ।** बांग्लादेश में छात्र और स्क्रैप का काम करने वाले लाल चंद उर्फ सोहाग की हत्या के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा है। दो दिन पहले ढाका में उसकी हत्या हुई थी। न्याय की मांग करते हुए ढाका में लोग सड़क पर उतर आए हैं। ढाका में सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज (मिटफोर्ड) अस्पताल के बाहर दिनदहाड़े लाल चंद उर्फ सोहाग की हत्या हुई थी। कथित तौर पर बुधवार शाम करीब 6 बजे अस्पताल के तीसरे गेट के पास कई लोगों ने मिलकर लोहे और सीमेंट के टुकड़ों से सोहाग को बेरहमी से मारा। ईंटों-पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद हमलावर उसके बेजान शरीर को घसीटकर सड़क पर ले गए, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने अपनी क्रूरता

जारी रखी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कथित तौर पर जबरन वसूली इसकी मुख्य वजह थी। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की युवा शाखा, जुबो दल के सदस्यों पर इस लिंचिंग में शामिल होने और जबरन वसूली के विवाद में हमला करने का आरोप है। लाल चंद उर्फ सोहाग के साथ क्रूरता का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी।

इस हत्याकांड के बाद ढाका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्रों में गुस्सा है। ढाका यूनिवर्सिटी (डीयू), बांग्लादेश इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी (बीयूईटी), जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी, और राजशाही यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश स्टूडेंट्स राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष बिन यामिन ने ढाका ट्रिब्यून% से कहा, ÷सोहाग की हत्या के खिलाफ उसी तरह सड़कों पर हैं, जैसे वो पहले अवामी लीग के समय में हुआ करते थे। बीएनपी अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही। जो कभी खुद पीड़ित थे, अब वही उत्पीड़क बन गए हैं।

डीयू के छात्र एबी जुबैर ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की और बीएनपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि वो देश को अपराधियों का अड्डा बना रहे हैं। उन्होंने कहा, बीएनपी नेता और कार्यकर्ता देशभर में जबरन वसूली, बलात्कार और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि पिछले दस महीनों में लगभग 100 हत्याओं के लिए बीएनपी जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक मौत की जांच की जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए।

## कुमार मंगलम बिड़ला यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में हुए शामिल

एजेंसी

**नई दिल्ली।** आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। वह निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी काम करेंगे। अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला उसके निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति में शामिल हो गए हैं। कुमार मंगलम बिड़ला निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी काम करेंगे। यूएसआईएसपीएफ ने एक बयान में कहा कि आदित्य बिड़ला समूह अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय ग्रीनफील्ड निवेशक है, जिसका निवेश 15 अरब यूएस डॉलर से अधिक है। ये समूह धातु, कार्बन ब्लैक और रसायन जैसे क्षेत्रों में 15 राज्यों में कार्यरत है। कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा, यूएसआईएसपीएफ की कार्यकारी समिति में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत कम समय में यूएसआईएसपीएफ अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आकार देने और मजबूत करने में एक मजबूत ताकत बन गया है। दोनों देशों के बीच संवाद, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देने में इसके योगदान ने एक सार्थक बदलाव लाया है।

## स्टॉक मार्केट में मेटा इंफोटेक की धमाकेदार एंट्री, प्रीमियम लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

**नई दिल्ली।** बैंकिंग, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग समेत अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी मेटा इंफोटेक के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 161 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 64 रुपये यानी 39.75 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 225 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर उछल कर 236.25 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 46.74 प्रतिशत का मुनाफा हो गया। इंफोटेक का 80.18 करोड़ रुपये का आईपीओ 4 से 8 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 155.28 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 20.04 करोड़ रुपये के 12.45 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर वेणुगोपाल पेरी ने 60.13 करोड़ रुपये के 37.35 लाख शेयरों की ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बिक्री की है।

## महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

**नई दिल्ली।** घरेलू सर्राफा बाजार में आज तेजी का रुख है। सोना आज 760 रुपये से 830 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में भी आज 1,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक की तेजी आई है। भाव में उछाल आने की वजह से आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 99,000 रुपये से लेकर 99,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 90,750 रुपये से लेकर 90,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 99,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 90,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 99,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

## रामगढ़ में सैमसंग ने एआई फीचर के साथ लॉन्च किया एफ सीरीज टीवी

**रामगढ़।** सैमसंग अपने नई तकनीक के लिए जाना जाता है। जिसकी वजह से ग्राहकों का ध्यान उस ओर बरबस चला जाता है। इस बार सैमसंग ने एआई फीचर के साथ एफ सीरीज टीवी लॉन्च किया है। गुरुवार को रामगढ़ में नारायणी परिसर में स्थित नेशनल एजेंसी में सैमसंग कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर सैमसंग के ब्रांच हेड मिथलेश तिवारी, एएसएम प्रियंक, आरएसओ प्रफुल्ल कुमार, डिस्ट्रीब्यूटर रवि अग्रवाल सैमसंग एक्सक्लुसिव डीलर आशीष मित्तल मौजूद थे। आधुनिक तकनीक से लैस सैमसंग एफ सीरीज की टीवी में एआई की सुविधा उपलब्ध है, जो नॉर्मल पिक्चर्स को भी 4-के में बदल देगा। साथ ही साथ ऑटोमेटिक साउंड एडजस्टमेंट की सुविधा ग्राहकों को बार-बार रिमोट के उपयोग से छुटकारा दिला देगी। नई फीचर के साथ सैमसंग ने इस टीवी का कंट्रोल वाई-फाई से कनेक्ट कर दिया है। टीवी को घड़ी और मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है।

# क्रिप्टोकरंसी मार्केट में तेजी का रुख, पहली बार एक करोड़ रुपये के पार पहुंचा बिटकॉइन

एजेंसी

**नई दिल्ली।** दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन ने आज पहली बार एक करोड़ रुपये के स्तर को पार करके नया इतिहास रच दिया। भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे बिटकॉइन 1,18,033 डॉलर यानी करीब 1.01 करोड़ रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बताया जा रहा है कि अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ में हुए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट और दुनिया के कई बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी की वजह से इस क्रिप्टोकरंसी की कीमत में अचानक इतनी तेजी आई है। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का कहना है कि बिटकॉइन ने 1,18,000 डॉलर के स्तर को पार करके ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है। उनका मानना है कि अगर बाजार की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ तो बिटकॉइन जल्दी ही 1,25,000 डॉलर के स्तर

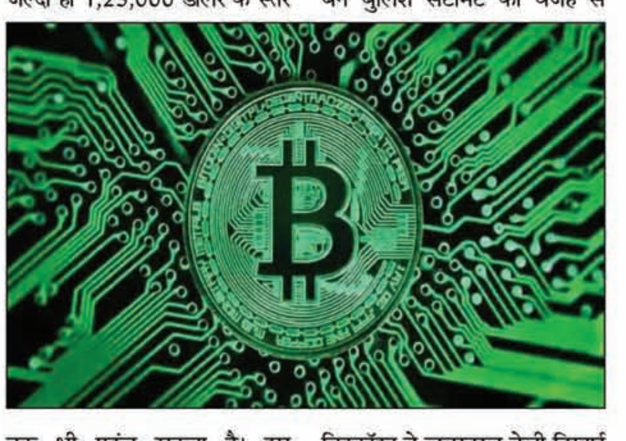

तक भी पहुंच सकता है। इस क्रिप्टोकरंसी ने अप्रैल के महीने में ही कंसोलिडेशन का सामना किया था, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी और क्रिप्टो मार्केट में बने बुलिश सेंटीमेंट की वजह से बिटकॉइन ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। इस साल जनवरी में 1 लाख डॉलर का आंकड़ा छूने के बाद अप्रैल के महीने में बिटकॉइन 75,000 डॉलर के स्तर तक गिर गया था। इस गिरावट के बाद क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर तेजी का रुख बनना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इस क्रिप्टोकरंसी ने एक बार फिर 1 लाख डॉलर के स्तर को पार करने में सफलता हासिल कर ली। बिटकॉइन की तेजी की वजह से इसके मार्केट कैप ने ताइवानी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिटकॉइन के टोटल होल्डिंग का 74 प्रतिशत हिस्सा फिलहाल लॉन्ग टर्म होल्डर्स (निवेशकों) के पास है, जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स की हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब इस क्रिप्टोकरंसी की मजबूती के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को समझा जाता है।

## कुमारस्वामी ने पीएम ई-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की

एजेंसी

**नई दिल्ली।** केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) को प्रोत्साहित करने की योजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि यह पहली बार है कि केंद्र सरकार ने देश को स्वच्छ और टिकाऊ माल ढुलाई गतिशीलता में परिवर्तन में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए समर्थन योजना शुरू की गई है। यह योजना प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार पर निर्भर करेगा और अधिकतम 9.6 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में एकमुश्त कटौती के रूप में प्रदान किए जाएंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से ओईएम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ माल ढुलाई गतिशीलता में तेजी लाना है। नई शुरू की गई इस योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत परिभाषित एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी मांग प्रोत्साहन योजना लागू होंगी। एन2 श्रेणी में सकल वाहन वाले ट्रक शामिल हैं, प्रोत्साहन केवल एन3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर्स पर ही लागू होंगे। इसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, निर्माता एक व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी प्रदान करेंगे। इसमें पांच साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी शामिल होगी, जबकि वाहनों और मोटरों के लिए वारंटी पांच साल या 2.5 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगी।

# व्यापारियों को इस वर्ष राखी पर 17 हजार करोड़ के व्यापार के उम्मीदः कैट

एजेंसी

**नई दिल्ली।** इस वर्ष 9 अगस्त को भारत की अनुपम संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक भाई-बहन का पवित्र पर्व 'रक्षाबंधन' देशभर में मनाया जाएगा। इस बार राखी का त्यौहार विशेष है, क्योंकि इसी दिन - भारत छोड़ो आंदोलन' की वर्षगांठ भी है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देशभर के व्यापारियों से आग्रह किया है कि वो इस बार राखी त्यौहार को 'राष्ट्रभक्ति राखी उत्सव' के तौर पर मनाएं। कैट की ओर से जारी एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष राखी पर देशभर में करीब 17 हजार करोड़ रुपये का व्यापार होने की संभावना है। चांदनी चौक से सांसद तथा कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने जारी बयान में कहा कि एक ओर जहां यह दिन भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होगा, वहीं दूसरी ओर देशभक्ति की भावना को भी जीवंत करेगा। इस अनूठे संयोग को देखते हुए देशभर के व्यापारी वर्ग ने बड़े पैमाने पर राखी के त्यौहार पर राखी की बिक्री के

लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं के शौर्य और वीरता को सम्मान देने के लिए कैट की पहल पर देशभर से महिला उद्यमी तीनों सेनाओं के सैनिकों को राखियां भेजकर इस बात का एहसास कराएंगी कि सारा देश उनके साथ है। कैट इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सैनिकों के लिए उनको राखियों की एक खेप भी सौंपेगा। खंडेलवाल ने कहा कि कैट को इस वर्ष राखी त्यौहार के मौके पर लगभग 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यापार होने की उम्मीद है। वहीं, मिठाइयां एवं ड्राई फ्रूट, गिफ्ट पैक, हैम्पर्स, सजावट सामग्री, परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, पूजा सामग्री और पैकेजिंग आदि का भी करीब 4 हजार करोड़ रुपये का व्यापार का अनुमान है। कैट ने देशभर के व्यापार मंडल, स्थानीय बाजार संघ और ट्रेड एसोसिएशन को इस बार राखी को 'राष्ट्रभक्ति राखी महोत्सव' के रूप में भी मनाने का आवाहन किया है। कैट की वेद एवं धार्मिक कमेटी के चेयरमैन तथा प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्री दुर्गेश तारे ने बताया कि रक्षा बंधन का पर्व भद्रा रहित व अपराह्न काल में मनाने का शास्त्रीय विधान है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व प्रातःकाल से दोपहर 1.38 मिनट तक ही मनाना उत्तम रहेगा क्योंकि यह समय भद्रा से मुक्त एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त है।

# डॉलर की तुलना में 15 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** ट्रेड टैरिफ की अनिश्चितता और इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों द्वारा जमकर की गई बिकवाली के कारण आज भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर की तुलना में गिरावट का शिकार हो गई। आज रुपया डॉलर की तुलना में 15 पैसे की कमजोरी के साथ 85.79 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुआ। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को भारतीय मुद्रा 85.64 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ की थी।इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की कमजोरी के साथ 85.76 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। दिन के कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए डॉलर की मांग बढ़ने पर रुपया 27 पैसे फिसल कर 85.91 के स्तर तक भी आ गया था, लेकिन इसके बाद डॉलर की आवक बढ़ने पर रुपया सुधर कर 85.78 के स्तर तक पहुंच गया। अंत में रुपया पिछले बंद भाव से 15 पैसे की गिरावट के साथ 85.79 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुआ।

भारतीय मुद्रा रुपये ने डॉलर के अलावा ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले मजबूती दिखाई। आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 30 पैसे की मजबूती के साथ 116.25 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह यूरो की तुलना में रुपया आज 18 पैसे की मजबूती के साथ 100.29 के स्तर पर पहुंचने में सफल रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमजोर वैश्विक संकेतों और ग्लोबल मार्केट में अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की वजह से बनी अनिश्चितता के कारण मुद्रा बाजार में भी संभल कर कारोबार हो रहा है। अमेरिका द्वारा ब्राजील और कनाडा पर टैरिफ में बढ़ोतरी किए जाने के कारण अनिश्चितता और बढ़ गई है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी सुधार होता हुआ नजर आने लगा है, जिसकी वजह से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा पर दबाव बढ़ गया है। खुराना सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ रवि चंदर खुराना का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन की वजह से हर ओर बिकवाली का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की मांग भी काफी अधिक हो गई है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में रुपये की कीमत में डॉलर की तुलना में थोड़ी और गिरावट आ सकती है।

# डीजीजीआई बेंगलुरु इकाई ने 266 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों वाली छह फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश किया

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने एक मामले की जांच के दौरान नई दिल्ली में 6 से अधिक परिसरों में तलाशी ली। अधिकारियों ने तलाशी के दौरान 266 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के फर्जी चालानों का खुलासा किया, जिसमें फर्जी कंपनियों से 48 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाना और उसे आगे बढ़ाना शामिल था। वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि जीएसटी की खुफिया शाखा डीजीजीआई ने दिल?ली शहर में छह परिसरों की तलाशी ली और 266 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और फर्जी कंपनियों से 48 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी पारित करने का खुलासा किया है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय

की बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों द्वारा बेंगलुरु में शुरू की गई एक मामले की जांच में पाया गया कि बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के 4 कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति दिखाई है। मंत्रालय ने बताया कि मास्टरमाइंडों ने बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के फर्जी कंपनियां बनाईं, कारोबार बढ़ाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग की, एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया और आईटीसी धोखाधड़ी में लिप्त रहे। वित?त मंत्रालय के मुताबिक जांच से पता चला है कि बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के चार कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति दिखाई है। इन कंपनियों के परिसरों की तलाशी के दौरान मुख्य आरोपित के परिसरों से मूल दस्तावेज़, जैसे चालान और मुहरें, बरामद की गईं।इस मामले के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी आईटीसी के उपयोग से जीएसटी धोखाधड़ी के ऐसे पैटर्न का पता चलने के बाद डीजीजीआई ने सेबी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए हाल ही में सेबी के साथ विशिष्ट जानकारी साझा की है।

## देश का विदेशी मद्रा भंडार तीन अरब डॉलर घटकर 699.74 अरब डॉलर पर

एजेंसी

**मुंबई।** अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर झटका लगने वाली खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार चार जुलाई को समाप्त हफ्ते में 3.05 अरब डॉलर घटकर 699.74 अरब डॉलर रह गया है। इससे पिछले हफ्ते के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.85 अरब डॉलर बढ़कर 702.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि चार जुलाई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का एक

प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.54 अरब डॉलर घटकर 591.29 अरब डॉलर रह गईं। इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 34.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 84.85 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के मुताबिक चार जुलाई को समाप्त हफ्ते में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 3.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.87 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 10.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.74 अरब डॉलर हो गया।देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 के अंत में बढ़कर अबतक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 704.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।

# उद्योगों से जुडे ऋण एवं व्यवसाय का पहला एक्सपो समृद्धि कॉन्क्लेव 1-3 अगस्त तक भारत मंडपम में

एजेंसी

**नई दिल्ली।** देश का पहला ऋण एवं व्यवसाय एक्सपो समृद्धि कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 1 से 3 अगस्त तक राजधानी के भारत मंडपम में होगा। यह सम्मेलन समावेशी वित्तीय सशक्तिकरण और उद्यमशीलता के पुनरुत्थान की दिशा और 20247 विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक साबित होने वाला है कॉन्क्लेव की समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ. राजीव दुबे ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, यह केवल आयोजन नहीं है, बल्कि यह हर उस उद्यमी के आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय आंदोलन है, जो महत्वाकांक्षी होने के बावजूद पहुंच से वंचित है। समन्वय समिति की उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों, व्यावसायिक

समाधान प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों को एक ही मंच पर लाएगा, जिससे अभूतपूर्व वित्तपोषण, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और सहयोग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केकेजीए पार एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड, सागा, कैट, एआईएआई, हाउस ऑफ एमएलएमसी, एफएम रेडियो मिर्ची और ग्राफिसैड्स की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, विकास पूंजी को खोलना और एमएसएमई, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और देश के महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करना है। सीए कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए समृद्धि कॉन्क्लेव एमएसएमई के एक बड़े समूह के साथ सीधे जुड़ने और उनके ऋण वितरण लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने का मौका देगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के तीन दिवसीय सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा होगी। गुप्ता ने बताया कि 200 से अधिक प्रदर्शकों और 60 हजार से अधिक आगंतुकों के साथ यह आयोजन भारत के वित्तीय और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला बनने के लिए तैयार है।

# आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आधुनिक और कुशल परीक्षण ढांचा तैयार करेगा केंद्र : पंकज चौधरी

एजेंसी

**नई दिल्ली।** केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आधुनिक और कुशल परीक्षण ढांचा तैयार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक आधुनिक औ कुशल परीक्षण ढांचा बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो आर्थिक विकास, अनुपालन और व्यापार में आसानी का समर्थन करता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने नई दिल्ली के पूसा परिसर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) के सी. सुब्रमण्यम सभागार में निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। व्यापार सुविधा सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

(सीआरसीएल), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने किया है। इस अवसर पर सीबीआईसी के सदस्य (कर नीति और कानूनी) विवेक रंजन और सीबीआईसी के सदस्य (सीमा शुल्क) सुरजीत भुजबल भी उपस्थित थे।

## केंद्र ने इरेडा बॉन्ड को धारा 54ईसी के तहत कर लाभ का दर्जा दिया

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण करने वाली कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के बॉन्ड को आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत कर-बचत का दर्जा प्रदान किया है। ये अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी हो गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्ड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत 'दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति' के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कम लागत पर धन जुटाने में सुविधा होगी तथा निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर में छूट मिलेगी। मंत्रालय के मुताबिक सीबीडीटी की अधिसूचना के अनुसार पांच वर्षों के बाद भुनाए जाने वाले और अधिसूचना तिथि को या उसके बाद आईआरईडीए द्वारा जारी किए गए बॉन्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अंतर्गत कर छूट के लिए पात्र होंगे, जो निर्दिष्ट बॉन्ड में निवेश पर पूंजीगत लाभ कर में छूट प्रदान करता है। इन बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग विशेष रूप से उन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

# लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों को 1 दिन में 3.63 लाख करोड़ की चपत

एजेंसी

**नई दिल्ली।** घरेलू शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। पहले आधे घंटे के कारोबार में खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण इन दोनों सूचकांकों की गिरावट बढ़ती चली गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.83 प्रतिशत और निफ्टी 0.81 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।आज दिनभर के कारोबार के दौरान आईटी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में लगातार बिकवाली होती रही। इसी तरह बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, टेक और मेटल इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयरों में आज खरीदारी होती रही। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 456.62 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 460.25 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 3.63 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,165 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,557 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,450 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 158 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,629 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 854 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,775 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 8 शेयर बढ़त के साथ और 22 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 12 शेयर हरे निशान में और 38 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 369.52 अंक की कमजोरी के साथ 82,820.76 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाने की कोशिश की, जिससे पहले आधे घंटे के कारोबार में ये सूचकांक ओपनिंग लेवल से करीब 220 अंक के रिकवरी करके 83,040.74 अंक तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया। लगातार हो रही बिकवाली के कारण सेंसेक्स थोड़ी देर में ही बड़ी गिरावट का शिकार हो गया। आज का कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 748.03 अंक की कमजोरी के साथ 82,442.25 अंक के स्तर तक गिर गया था। हालांकि अंत में इंट्रा-डे सेटलमेंट की वजह से हुई खरीदारी के कारण सेंसेक्स निचले स्तर से करीब 60 अंक की रिकवरी करके 689.81 अंक की गिरावट के साथ 82,500.47 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह एनएसई के निफ्टी ने आज 99.75 अंक फिसल कर 25,255.50 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक ओपनिंग लेवल से करीब 70 अंक की रिकवरी करके 25,322.45 अंक तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से निफ्टी भी गिरता चला गया। लगातार हो रही बिकवाली के कारण आज का कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 226.25 अंक की गिरावट के साथ 25,129 अंक के स्तर तक पहुंच गया।

infodivyadelhi@gmail.cm

## आमिर खान की सितारे जमीन पर के बाद

# जेनेलिया देशमुख

## की बल्ले-बल्ले, अजय देवगन की बड़ी फ्रेंचाइज में वापसी

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इस फिल्म में आमिर के अपोजिट जेनेलिया देशमुख नजर आईं. वे काफी समय के बाद किसी बड़ी फिल्म में अहम रोल प्ले करती नजर आईं. हालांकि एक्ट्रेस ने खुद भी ये बताया था कि उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए ऑडिशन भी देने पड़े थे. अब जेनेलिया देशमुख को इस फिल्म में काम करने का एक और बड़ा फायदा मिला है. उनकी वापसी सक्सेसफुल फिल्म मस्ती में होने जा रही है जिसके पहले पार्ट में अजय देवगन भी थे. एक्ट्रेस इस फिल्म के पहले पार्ट का हिस्सा थीं. और अब वे फिल्म के चौथे पार्ट में नजर आने जा रही हैं.दरअसल सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मस्ती के चौथे पार्ट की शूटिंग चल रही है. पहले तो इस फिल्म की शूटिंग में जब जेनेलिया नजर आईं तो लोगों को यही डाउट हुआ कि वे सिर्फ फिल्म की शूटिंग देखने आई हुई हैं. लेकिन बाद में सबकुछ क्लियर हो गया. लेकिन अब वे खुले तौर पर शूटिंग की रिहर्सल करती और खुद शूटिंग करती भी नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के साथ इस फिल्म में उनके हसबेंड रितेश देशमुख भी नजर आएंगे.

**जेनेलिया ने कर ली है वापसी**

दरअसल शादी के बाद से जेनेलिया ने ज्यादा फिल्में नहीं की और इस दौरान वे अपनी फैमिली संग बिजी रहीं. लेकिन सितारे जमीन पर से वापसी के बाद से ऐसा लग रहा है कि जेनेलिया थमने के मूड में नहीं हैं. हाल ही में उनकी फिल्म गनस्टार जी9 की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें अपारशक्ति खुराना और इमरान हाशिमी नजर आएंगे. वहीं दूसरी तरफ अब वे मस्ती 4 का भी हिस्सा हैं. मतलब कि जेनेलिया के फैंस की तो बल्ले ही बल्ले है.

**कैसा रहा सितारे जमीन पर का कलेक्शन**

जेनेलिया की बात करें तो वे सितारे जमीन पर फिल्म में आमिर खान की वाइफ के रोल में नजर आईं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की सराहना हो रही है. आमिर की इस फिल्म को जनता का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने जहां एक तरफ भारत की बात करें तो भारत में इस फिल्म ने 183 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं अगर फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 236 करोड़ रुपए कमाए हैं.

# श्रुति हासन

## ने रजनीकांत को कहा चालाक, बोलीं- 'कुली' में उनके साथ काम किया तो पता चला...

कमल हासन की बेटी श्रुति हासन ने साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कुली' में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम किया है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनका रजनीकांत के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा। श्रुति ने बताया कि फिल्म करने से पहले वह रजनीकांत को अपने पिता कमल हासन के नजरिए से जानती थीं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें रजनीकांत का एक अलग रूप देखने को मिला। श्रुति ने कहा कि रजनीकांत बहुत शार्प और चतुर हैं।

**रजनीकांत के साथ काम करके कैसा लगा ?**

श्रुति ने कहा, मेरे पिता और रजनीकांत तमिल सिनेमा के दो स्तंभ हैं। फिल्म में उनके साथ काम करने से पहले मैं उन्हें जनता के नजरिए से जानती थी। मुझे पता है कि लोगों को ये लगता था कि मैं उनके करीब रही हूं, लेकिन असल में मैं उन्हें अपने पिता के नजरिए से जानती थी। शूटिंग के दौरान उन्हें करीब से जानना मेरे लिए एक अलग अनुभव था।

**कैसे हैं रजनीकांत ?**

श्रुति ने रणवीर इलाहाबादिया को दिए पॉडकास्ट में कहा, कुली में उनके साथ काम किया तो पता चला कि उनमें कई अनोखे गुण हैं। वह चतुर और तेज हैं, लेकिन वह बहुत गर्मजोशी से भरे भी हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत अच्छे हैं और उनसे बात करना आसान है। वह सेट पर हमेशा अपने साथ अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं और हर कोई उनके साथ काम करके खुश होता है।

**कब आएगी 'कुली' ?**

फिल्म 'कुली', जिसका निर्देशन लोकेश कनगराज कर रहे हैं, 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रजनीकांत और श्रुति हासन के अलावा नागार्जुन, उपेंद्र, सौबिन शाहीर और सथ्याराज जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। इसके साथ ही, आमिर खान भी फिल्म में नजर आएंगे।

## जब सौतन से जूही चावला ने की मिन्नतें...33 साल पुराना वो गाना, जिसने सिनेमा हॉल में कर दी आंसुओं की बारिश

90 की दिग्गज एक्ट्रेस जूही चावला आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई खूबसूरत फिल्में दी हैं. एक्ट्रेस की अदाकारी में इतना दम था कि दर्शकों उनके साथ हंसते और रोया करते थे. साल 1992 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई जूही चावला की फिल्म 'बेवफा से वफा' ने अपनी कहानी और गानों के चलते सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया. आज भी लोग इस फिल्म के गाने सुनना पसंद करते हैं. फिल्म के एक गाने में जूही को अपनी सौतन से मिन्नतें करते हुए देखा जाता है. जब ये फिल्म देखने लोग सिनेमाघरों में पहुंचे तो एक्ट्रेस को फूट-फूटकर रोता देख खुद भी रोने लगे थे.

दरअसल जूही चावला ने 'बेवफा से वफा' में एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है, जो कहानी में मोड़ के चलते खुद अपने पति की दूसरी शादी करवाती है. ये किरदार जूही के सबसे इमोशनल किरदारों में से एक है. दूसरी पत्नी का किरदार एक्ट्रेस नगमा ने निभाया है. फिल्म का 'गाना हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा' में जूही अपने पति और दूसरी पत्नी नगमा से हाथ जोड़कर और रोते हुए मिन्नतें करती हैं कि वो घर को छोड़कर न जाएं.

**जूही चावला के दर्द ने लोगों का दिल छू लिया**

ये एक बेहद ही इमोशनल गाना था, जिसमें जूही का किरदार रो-रोकर अपना बुरा हाल कर लेता है. ये गाना उस वक्त बॉलीवुड के सबसे इमोशनल गानों की लिस्ट में टॉप पर था. एक्ट्रेस के मासूम हाव-भाव और आंसुओं से भरी आंखों ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया. जूही चावला, जिन्हें ज्यादातर फिल्मों में उनके चुलबुले और हल्के-फुल्के सीरियस रोल्स के लिए पसंद किया जा रहा था, उन्हें इस तरह रोता-तड़पता हुआ देख दर्शक भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए. जूही को उनके काम के लिए खूब तारीफें मिलीं.

**फिल्म का वो गाना जिसने देश को रुला दिया**

'घर छोड़ कर ना जाओ कहीं, तुम्हें घर ना मिलेगा गाना' फिल्म 'बेवफा से वफा' का इमोशनल कोर बन गया. गाने में जूही का किरदार अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी से घर न छोड़ने की विनती करता है, ये देख लोगों का दिल टूट गया था. बताया जाता है कि इस गाने के बोल और जूही चावला के दिल को छूने वाले एक्सप्रेशन से प्रभावित होकर दर्शक सिनेमाघरों में ही रो पड़े.

## अजय देवगन के फिंगर स्टेप पर पत्नी काजोल ने उड़ाया मजाक, हंसी पर नहीं रख पाई काबू, कह दी ऐसी बात

अजय देवगन अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, जल्द ही उनकी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' थिएटर में दस्तक देने वाली है. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म का एक गाना रिलीज कर दिया है, जो कि पहला तू दूजा तू है. गाना रिलीज होते ही ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि लोग गाने से ज्यादा इसके डांस स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं. दरअसल, इस गाने में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर का हुक स्टेप उंगलियों से किया गया है. सोशल मीडिया पर इसे काफी ट्रोल किया जा रहा है और अब काजोल का भी इस पर मजेदार रिएक्शन सामने आया है.

अजय देवगन ज्यादातर फिल्मों के गानों में अपने डांस स्टेप्स को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं. लेकिन 'सन ऑफ सरदार 2' में एक्टर का फिंगर-स्टेप देख लोग खूब मजा ले रहे हैं. हाल ही में काजोल ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए अपने पति अजय देवगन को ट्रोल किया है. जब एक्ट्रेस से इस गाने के स्टेप के बारे में पूछा गया, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. काजोल ने अजय को ट्रोल करते हुए उन्हें बॉलीवुड का सबसे बेहतरीन डांसर बताया है.

**'इंडस्ट्री के बेस्ट डांसर्स में से एक'**

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिस मालिनी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें काजोल अजय देवगन और मृणाल के फिंगर स्टेप के बारे में सवाल किया गया. इस पर एक्ट्रेस ने मजेदार रिएक्शन देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट डांसर्स में से एक हैं, क्योंकि अब वह एकलौते ऐसे एक्टर हैं जो अपनी उंगलियों से डांस कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने पहले के वक्त को याद करते हुए कहा एक्टर को सबसे स्मार्ट डांसर भी करार दिया है.

**पहले भी एक्टर हुए हैं ट्रोल**

काजोल ने कहा कि पहले तो वो चल कर आते थे, तो म्यूजिक उस हिसाब से बनती थी, लेकिन अब वो सिर्फ उंगलियों से गिनती करते हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब अजय देवगन किसी गाने में अपने डांस स्टेप को लेकर ट्रोल हुए हैं. इससे पहले उन्होंने 'तेरी धूम धाम' गाने में भी फिंगर से ही स्टेप किया था. वहीं 'सन ऑफ सरदार 2' की बात करें, तो फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, विजय कुमार अरोड़ा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज होगी.

**न्यूज फ्लैश**

## फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की छात्रा के आत्महत्या के प्रयास पर महिला कांग्रेस ने उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की

दिव्य दिल्लीः फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय के शिक्षा विभाग की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या के प्रयास के संबंध आज कांग्रेस भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी बहिनीपति ने कहा कि पीड़ित छात्रा को उक्त महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष समीर साहू द्वारा लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उक्त महाविद्यालय में कोई स्थायी अध्यक्ष न होने के कारण, छात्रा ने उपाध्यक्ष से शिकायत की और अंततः निराश होकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। शरीर के 90 हिस्सों में जलने से पीड़ित उक्त छात्रा गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। श्रीमती बहिनीपति ने कहा कि यह घटना ओडिशा में शिक्षा, प्रशासन और महिला सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण विफलता को प्रमाणित करती है। पीड़िता के आत्महत्या के प्रयास के लिए महाविद्यालय प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। महिला ने कहा कि इसलिए, कांग्रेस उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, कार्यवाहक अध्यक्ष की गिरफ्तारी और एक अनुभवी महिला न्यायाधीश से न्यायिक जाँच की माँग करती है। महिला कांग्रेस नेता बहिनी पति ने कहा कि पीड़िता से मिलने गई एबीवीपी की प्रदेश सदस्य को अभद्र व्यवहार करते हुए महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रवेश नहीं करने दिया गया और पूछा कि क्या यही एबीवीपी का शिष्टाचार है।छात्रा की शिकायत के बाद, कॉलेज ने एक समिति का गठन किया, जो पहले यूजीसी के नियमों के अनुसार गठित होनी थी, लेकिन छात्रा की शिकायत के बाद इसका गठन किया गया। चूँकि कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष ने इस घटना की उचित ज़िम्मेदारी नहीं ली है। नारी न्याय बहिनी की प्रोफेसर (डी) गायत्री विश्वाल ने कहा कि आत्महत्या करने वाली छात्रा ने सांसद, विधायक और पुलिस को अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी दी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पीसीसी प्रवक्ता सोनाली साहू ने कहा कि छात्रा ने ट्वीट के माध्यम से सीएमओ, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य उच्च शिक्षा मंत्री और महिला आयोग को घटना की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। पीड़िता ने न्याय पाने के लिए कॉलेज अध्यक्ष, पुलिस स्टेशन, बालासोर के सांसद, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से संपर्क किया था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अंत में, निराश होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। हालांकि वह एबीवीपी छात्र संघ की सदस्य थी, लेकिन उसका अपना संगठन और सरकार उसकी रक्षा नहीं कर सकी। इसलिए, ओडिशा के सभी परिसरों में छात्र आतंक की स्थिति में हैं। ओडिशा में सरकारी और निजी शिक्षा परिसरों में महिलाएं असुरक्षित हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, जो परिसर में छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे दें और सांसद प्रताप सारंगी को भी जांच के दायरे में लाया जाए।

## श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पठानकोट में 3.5 लाख पौधे लगाए जाएँगे

**दिव्य दिल्ली : कंवल रंधावा (पठानकोट)**

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए और ह्यहिंद की चादरह्य श्री गुरु तेग बहादुर जी की महान विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप, पठानकोट वन प्रभाग ने उनके 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक बड़े वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की है। यह जानकारी पठानकोट के उपायुक्त श्री आदित्य उप्पल ने दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम 3.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पठानकोट में यह अभियान प्रकृति संरक्षण के प्रति पंजाब सरकार और वन विभाग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। गुरु जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पठानकोट वन प्रभाग की 19 नर्सरियों में लगभग 20 लाख पौधों का भंडार उपलब्ध है, जिसमें 40-45 प्रकार के पौधे शामिल हैं। इस वर्ष प्रत्येक नर्सरी में पलाश, महुआ, झंड और कीकर जैसी 5 नई देशी किस्में शामिल की गई हैं। कोई भी नागरिक, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठन इन नर्सरियों से 2 रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे प्राप्त कर सकता है। पौधारोपण अभियान वन क्षेत्रों, सरकारी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों, अंतर्राष्ट्रीय भूमि और सड़कों के किनारे किया जाएगा। शीशम, नीम, अर्जुन, तू, आम, बिहड़ा, कहार, आंवला और बांस जैसी देशी और पर्यावरण के लिए लाभदायक किस्मों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जैव विविधता को बढ़ाया जा सके और स्थायी हरित क्षेत्र बनाए जा सकें। पठानकोट वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी, श्री धर्मवीर दैरू, आईएफएस, ने बताया कि इस वर्ष ६ लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3.5 लाख पौधे वन विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं और मनरेगा के तहत लगाए जाएँगे, जिनमें 60 से अधिक नए नानक उद्यानों की स्थापना भी शामिल है। शेष पौधे सेना, बीएसएफ, अन्य सरकारी विभागों और आम जनता को दिए जाएँगे। आने वाले दिनों में ज़िले में विभिन्न स्थानों पर वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। श्री धर्मवीर दैरू ने कहा, ह्ययह पौधारोपण अभियान केवल पौधे लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि सद्भावना, साहस और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के बीज बोने के बारे में है - जो गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं में गहराई से निहित हैं।ह्य वन विभाग ने नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों से इस अभियान में भागीदार बनने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पठानकोट को हरा-भरा और स्वस्थ बनाने में योगदान देने की अपील की है।

## संत निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य है मानवता को जिंदा रखना- के धीमान

**दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)**

नूरपुर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन परिसर फतेहपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें संत निरंकारी मिशन के 78 श्रद्धालुओं द्वारा नि :स्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा की टीम ने रक्त एकत्रित किया।इस मौके पर जिला जोनल इंचार्ज कांगड़ा डॉक्टर के धीमान ने कहा कि संत निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य है मानवता को जिंदा रखना जिसके लिए समय-समय पर संत निरंकारी मिशन द्वारा कई तरह के मानवता से जुड़े कार्य किये जाते रहे हैं। कहा कि संत निरंकारी मिशन सदैव ही मानवता की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्तदान करके किसी की कीमती जिंदगी को बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण की स्वच्छता के लिए पौधे लगाने की भी अपील की है। उन्होंने रक्तदान शिविर को सफल बनाने पर जहां रक्तवीरों का आभार जताया तो वहीं उक्त शिविर में विभिन्न ड्यूटी निभा रही टीमों का धन्यवाद किया।

## भोआ में 3.70 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री लाल चंद ने दी सौगात

**दिव्य दिल्ली : कंवल रंधावा (पठानकोट)**

भोआ विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बारठ साहिब से खोबा, गोबिंदसरझबाबा श्री चंद जीझकोटली मुगल रोड की 5.42 किमी लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस सड़क पर करीब 3.70 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान का विशेष आभार जताया, जिन्होंने भोआ क्षेत्र की 74 सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य का जिम्मा उठाया है।कैबिनेट मंत्री ने बताया कि गुरुद्वारा श्री बारठ साहिब जाने वाली यह सड़क श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी खराब हालत से वर्षों से लोग परेशान थे। अब इस सड़क को 11 फीट पक्की सड़क बनाकर दोनों ओर इंटरलॉक टाइलों के साथ 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना ना सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करेगी।इस मौके पर जिला अध्यक्ष बीसी विंग पठानकोट नरेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार व राजिंदर भिल्ला, एसडीओ मंडी बोर्ड राकेश कुमार, सरपंच अश्वनी कुमार, पंचायत सदस्य और अन्य स्थानीय नेता व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## डी ए बी पट्टा जटियां में द्विदिवसीय टूर्नामेंट में क्रिकेट मैच सफलतापूर्वक संपन्न

**दिव्य दिल्ली : ऊषा जरियाल (जवाली)**

डी ए बी पब्लिक स्कूल, पट्टा जटियां में आयोजित द्विदिवसीय खेल टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज रविबार को क्रिकेट मैच बड़े ही उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने उत्कृष्ट खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। इस अबसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एआरओ डॉ रश्मि जमवाल रहीं। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में विशाल कटोच (प्रेक्षक) प्राचार्य डीएबी गोझू तथा मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष डी ए बी स्कूल चलवाड़ा उपस्थित रहे। वहीं, विशेष अतिथि राजेश्वर सिंह जो एचपीसीए द्वारा आयोजित कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी में मैनेजर हैं, ने खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल शर्मा ने सभी अतिथियों, प्रतिभागी टीमों, शिक्षकगण, आयोजक समिति और छात्रों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट के अंत में विजेता टीमों को मेडल और ट्रॉफी वितरित किए गए, जिससे खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी और गर्व की झलक देखने को मिली। पुरस्कार वितरण समारोह में सभी अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

## पर्यटन बिभाग की प्रॉपर्टी बेची नही बल्कि संचालन और रखरखाव के लिए निजी हाथों में सौंपी जाएगी

**दिव्य दिल्ली : विजय महाजन (नूरपुर)**

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की प्रॉपर्टियों औरओ एन्ड एम मॉडल को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों को लेकर निगम के निदेशक अंबर महाजन नेएक भेंट वार्ता मे कहा कि विपक्षी नेता यह दावा कर रहे हैं कि एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टियाँ बेची जा रही हैं, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। जिन प्रॉपर्टियों की बात हो रही है, उनके लिए केवल मॉडल ऑपरेशन और मैंटीनेन्स पर विचार किया जा रहा है जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, और सिर्फ उसका संचालन और रखरखाव कुछ समय के लिए किसी एजेंसी को सौंपा जाएगा।अंबर महाजन ने कहा कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे बिना प्रॉपर्टी बेचे उसमें बाहरी निवेश लाकर सुधार किया जा सकता है, सुविधाएँ बेहतर की जा सकती हैं और पर्यटन को नई ऊर्जा दी जा सकती है। यह कदम इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं, और कई संपत्तियाँ वर्षों से पूरी क्षमता में इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं।महाजन ने कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने हिमाचल को न तो बाढ़ जैसी आपदा के समय मदद दीऔर न ही पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को मजबूती देने के लिए कोई ठोस सहयोग दिया जबकि हिमाचल जैसा खूबसूरत और शांत राज्य, विश्व की पर्यटन राजधानी बनने की पूरी क्षमता रखता है ऐसे समय में उसे सहयोग की सख्त जरूरत है।महाजन ने कहा कि जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, यदि विपक्ष कह रहा है कि इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो यह बात भी पूरी तरह से निराधार है अगर भविष्य में कोई निर्णय होता भी है, तो सरकार उसी मॉडल को अपनाएगी जैसा टाटा और एयर इंडिया के बीच हुआ था जिसमें कर्मचारियों की नौकरियाँ और अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए थे।इसके अलावा, सरकार कोई भी नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेगी, पूरी रिसर्च करवाई जाएगी और हर पहलू पर गहराई से विचार किया जाएगा।

## सूद सभा चंडीगढ़ की ओर से लगाया गया वार्षिक मैंगो मेला

**दिव्य दिल्ली : शशि भूषण (पंचकुला)**

सूद सभा चंडीगढ़ की ओर से रविवार को सूद भवन सेक्टर 10, पंचकुला में वार्षिक "मैंगो फेस्टिवल 2025" का आयोजन किया गया। सूद-भवन सेक्टर 10, पंचकुला परिसर में लगाए गए इस मैंगो फेस्टिवल 2025 में ट्राईसिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला तथा आसपास के अन्य इलाकों से लगभग 100 से अधिक सूद परिवारों ने स्वादिष्ट आमों की विभिन्न किस्मों का आनंद लिया। इस मौके पर सूद सभा कि ओर से लाईफ मेंबरों के लिए तंबोला का भी आयोजन किया गया। मैंगो फेस्टिवल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता, आकर्षण का केंद्र रही।
सूद सभा, चंडीगढ़ के अध्यक्ष अश्वनी सूद, महासचिव सुधीर सूद तथा वित्त सचिव खुशविंदर सूद ने सूद बिरादरी की परंपराओं के महत्व के बारे में इस मेले के दौरान मौजूद सूद बिरादरी के लोगों का संबोधन किया। इस वर्ष मैंगो मेला 2025 की आयोजक कमेटी में संदीप, लोकेश सूद, सुमित सूद,संजय सूद, दीपक सूद तथा मुकेश सूद शामिल थे। सूद सभा चंडीगढ़ के प्रेस सैक्ट्री सचिन सूद और ज्वाइंट सचिव प्रेस मुकेश सूद ने बताया कि सूद सभा चंडीगढ़ की ओर से हर साल मौनसून सीजन के दौरान कोंट्रीब्यूटरी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें ट्राईसिटी चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली तथा साथ लगते अन्य शहरों से सूद बिरादरी के लोग बढ़-चढ़कर शामिल होते हैं। सूद सभा में मैंगो मेले का आयोजन सूद सभा के गठन यानी की 1959 से भी पहले का है उस समय सूद सभा के फाउंडिंग मेंबर्स अपने घरों से आम लाकर एकत्रित होकर परिवारों के साथ मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया करते थे जिसके बाद उन्होंने सूद सभा का गठन किया।

## श्रावण माह का दूसरा पावन दिवस होने पर सैंकंडों की संख्या में संगत ने

**दिव्य दिल्ली : कंवल रंधावा (पठानकोट)**

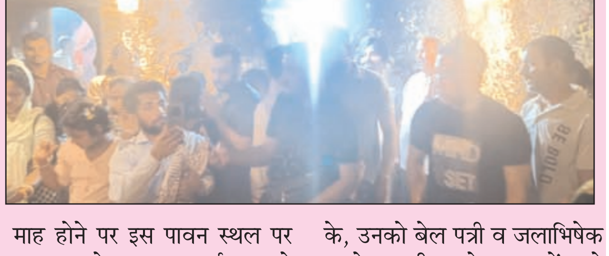

**श्रावण** माह का दूसरा पावन दिवस होने पर व रविवार का दिन होने पर बाबा मुक्तेश्वर मंदिर में सैंकंडों की संख्या में संगत ने पहुंच कर माथा टेका तथा गुफाओं के अंदर पांडवों की ओर से स्थापित पावन श्री शिवलिंग जी की पूजा अर्चना की। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, ठाकुर भीम सिंह, पूर्व सरपंच दिलवाग सिंह, अंकुश तनवाल, पुरषोतम सिंह, भाग सिंह, नरेश कुमार, सुरिंद्र कुमार ,पंडित हरि कृष्ण व अन्य ने बताया कि पावन श्रावण माह होने पर इस पावन स्थल पर स्नान करने व पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है, जिसके लिए अब प्रतिदिन भारी संख्या में संगत सुबह से ही यहां पर पहुंच कर, मंदिर कमेटी की ओर से बनाए हुए स्नानाघर में स्नान करके, पावन श्री शिवलिंग जी की पूजा अर्चना करके, उनको बेल पत्री व जलाभिषेक करके,अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पूजा अर्चन कर रहे है। मंदिर कमेटी ने बताया कि इस समय रावी नदी में लगातार पानी बढ रहा है, जिसके लिए कोई भी श्रद्धालु रावी नदी में स्नान करने के लिए न जाए।

## चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, विस्थापित परिवारों ने उठाई आवाज

**दिव्य दिल्ली : कंवल रंधावा (पठानकोट)**

शाहपुर कंडी बैराज बांध विस्थापित परिवारों ने अपने रोजगार व पुनार्वास मुआवजे की मांग को लेकर , चीफ इंजीनियर डैमज प्रशासन के कार्यालय के बाहर बैराज बांध विस्थापित संघर्ष कमेटी के पदाधिकारी व कामरेड जसवंत सिंह संधू की अध्यक्षता में बैठक की तथा आज 103वें दिन लगातार अपनी भूख हडताल भी जारी रखी। आज की भूख हडताल में मोहित शर्मा शाहपुर कंडी, सुनील कुमार शाहपुर कंडी, राकेश वर्मा कोट, साहिल सिंह कोट व नरेश सिंह झूं शामिल हुए। संघर्ष कमेटी के पदाधिकारी कामरेड जसवंत संधू, बलकार सिंह, पूर्व सरपंच सुरेश सुबंरिया, महिंद्र सिंह काहलों, सुरजीत सिंह, संजय अनोत्रा, रविंद्र बाबा, रोहित कुमार व अन्य ने बताया कि उनके विस्थापित परिवारों की ओर से पिछले 103 दिनों से लगातार अपना संघर्ष व भूख हडताल की जा रही है।

## विधायक विवेक शर्मा ने वैरी हटली गांव में 76वें वन महोत्सव का किया शुभारंभ

**दिव्य दिल्ली : ऊना**

**उपमंडल** बंगाणा की धुंधला पंचायत के वैरी हटली गांव में रविवार को 76वें वन महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विवेक शर्मा रहे, जिन्होंने पूजा-अर्चना के बाद 11 पौधे लगाकर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। डीएफओ सुशील राणा की अगुवाई में विधायक का शाल, टोपी और स्मृतिचिन्ह देकर स्वागत किया गया।अपने संबोधन में विवेक शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई वन महोत्सव योजना न केवल हरियाली बढ़ाने, बल्कि स्वयं सहायता समूहों व महिला मंडलों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में भी अहम कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना के तहत इन समूहों को पौधारोपण के लिए 2.40 लाख की सहायता दी जा रही है, साथ ही पौधों की देखभाल के आधार पर 40 हजार से 1 लाख तक का इनाम भी निर्धारित किया गया है।विधायक ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में 16,000 हेक्टेयर वन भूमि है, जिसे उपयोग में लाकर ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने वन क्षेत्रों में ऐसे पौधों को प्राथमिकता देने की बात कही जो ग्रामीणों की आजीविका को भी मजबूत करें।इसके साथ ही उन्होंने वैरी हटली गांव के श्मशान घाट के रास्ते की मरम्मत के लिए 2 लाख की राशि देने की घोषणा की और कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वे लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क में हैं, जिनमें से

## आत्म प्रज्ञा आश्रम बागनी में आज महा यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई

**दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)**

नूरपुर आत्म प्रज्ञा आश्रम बाघिनी नूरपुर में आज ऋग्वेद पारायण महायज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई है। प्रातः और सायम् दोनों समय तीन - तीन घंटे ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियां दी गई जिसमें नूरपुर, जसूर ,कंडवाल खज्जन,सुलियाली गही लगोड, भडवार, नागनी बाघनी ,नगरोटा बगवां, अलीगढ़, रोहतक से आर्य जनों ने भाग लिया। इस यज्ञ में धर्म मुनि क्रांतिकारी जी ने संन्यास की दीक्षा भी ली । वर्षा काल में यज्ञ से विशेष लाभ होता है। जहां वर्षा काल में सब कुछ सड़ने लगता है लोहा तक सड़ने लगता है ऐसे में विशेष व बड़े यज्ञों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पहले घरों में परंपरा थी कि लोग वर्षा काल में घर-घर में हवन करवाते थे अब यह परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं।हमें प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ करना चाहिए ।प्रतिदिन ना कर पाएं तो सप्ताह में एक बार करें, सप्ताह में ना कर पाएं तो पूर्णिमा अमावस्या पर करें, संक्रांति पर कर लें। तब भी ना करें तो ऋतु परिवर्तन पर अवश्य ही करें।ऋतु हर 2 महीने में बदलती है और ऋतु परिवर्तन पर रोग अधिक फैलते हैं और वर्षा ऋतु में तो और भी अधिक रोग होते हैं तो हमें बड़े-बड़े यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। चाहे हम सामूहिक रूप से अपनी गली ,मोहल्ले या चौराहों पर यज्ञों का आयोजन करें ।हमें यज्ञ किसी भी स्थिति में नहीं छोडना चाहिए ।

## तिरंगे में लौटे ए.एस.आई सुधीर कुमार का सैन्य सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

**दिव्य दिल्ली : कंवल रंधावा (पठानकोट)**

सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन के एएसआई सुधीर कुमार डढवाल, जो जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित अनंतनाग में तैनात थे, का 11 जुलाई को ड्यूटी के दौरान आए हृदयाघात से निधन हो गया। आज उनके पैतृक गांव तलवाड़ा गुजरां में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की पार्थिव देह जैसे ही गांव पहुंची, पूरा इलाका शोक में डूब गया। अनंतनाग से आई सैन्य टुकड़ी ने सहायक कमांडेंट वरिंदर कुमार के नेतृत्व में बिगुल की गूंज और हवा में गोलियों की सलामी के साथ सुधीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी।
शहीद के पिता रिटायर्ड हवलदार कर्म चंद, पत्नी जीवन, बेटा अंकुश, बेटी मुस्कान, भाई अजय और बहनों सीमा व शोभा ने आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए अंतिम दर्शन किए। सारा गांव पिछले दो दिनों से गमगीन था, किसी घर में चूल्हा नहीं जला।


Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397